* 20th Year
* Issue: 102
* 11.08.2026 (TUESDAY)
* ROURKELA
* R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
* (Pages-6)
* Price:2.00

e-paper-www.thekalingasamachar.com

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

गुरुजी की तस्वीर, हेमंत के खिलाफ तीर, सड़कों पर छात्र, विरोध की अनोखी भीड़

रांची १०/०८ (संवाददाता): झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की धांधली के खिलाफ उबला गुस्सा एक अनूठा विरोधाभास बयां कर रहा है। एक तरफ सड़कों पर उतरा युवाओं का सैलाब हेमंत सोरेन सरकार की ईंट से ईंट बजा रहा है, तो दूसरी तरफ उन्हीं के हाथों में मुज्यमंत्री के दिवंगत पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पोस्टर लहरा रहे हैं। भगत सिंह और डॉ. बीआर आंबेडकर के साथ शिबू सोरेन की तस्वीर थामे ये युवा साफ संदेश दे रहे हैं कि लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा से नहीं, बल्कि सज़ा के अहंकार में अपने ही पुरखों के आदर्शों को भूल बैठे मौजूदा नेतृत्व से है। राजनीति में ऐसे विरोध प्रदर्शनों के कई उदाहरण मिलते हैं, जहां सज़ाधारी दल की मूल विचारधारा पर तो सवाल नहीं उठाया जाता, लेकिन उसके मौजूदा नेतृत्व पर पार्टी के उन आदर्शों से भटकने का आरोप लगाया जाता है जिनका वह दावा करती है। जेएमएम के सह-संस्थापक और प्रमुख नेता रहे शिबू सोरेन 1980 के दशक से अलग आदिवासी राज्य झारखंड के आंदोलन के सबसे प्रमुख चेहरा थे। उनकी यह मांग साल 2000 में पूरी हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने बिहार से अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया। हालांकि शिबू सोरेन पर अपने दौर में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, लेकिन इसके बावजूद राज्य में खासकर आदिवासियों के बीच उनकी स्थिति हमेशा एक जननायक और सर्वमान्य नेता की बनी रही। राज्य के गठन और खासकर आदिवासी मुद्दों से खुद को अलग न करते हुए, प्रदर्शनकारियों ने सोरेन सीनियर की विरासत को उनके बेटे हेमंत की राजनीति से अलग रखा है। इस तरह, वे बेटे की सरकार की आलोचना करते हुए भी पिता का सज़्मान करते हैं।

यह तरीका नया नहीं है। महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना बालासाहेब ठाकरे का सज़्मान करती है, जबकि शिवसेना (यूबीटी) के उनके बेटे उद्धव पर हमला करती है और उन पर पिता की विरासत को कमजोर करने का आरोप लगाती है। बीजेपी भी बाला ठाकरे का सज़्मान करती है, जो वाजपेयी और एलके आडवाणी के समय में सहयोगी थे। जबकि उद्धव की कड़ी आलोचना करती है। नेताओं की पारिवारिक विरासत पर ध्यान दिया गया है। उन पर लगभग यह आरोप लगाया जाता है कि वे अपने पिताओं की विरासत को कमज़ोर कर रहे हैं। हालाँकि, यह पैटर्न अज़्सर राजनीतिक दलों और उनकी सोच के संदर्भ में भी लागू होता है, भले ही इसमें कोई सीधी पारिवारिक विरासत शामिल न हो। बीजेपी सरदार पटेल और नरसिज़्हा राव जैसी शज़्सियतों का सज़्मान करती है, जबकि जवाहरलाल नेहरू और नेहरू-गांधी परिवार में उनके वंशजों को अलग-थलग करके निशाना बनाती है। जिसका सीधा सा मकसद ये बताना है कि एक परिवार ने उस पुरानी और बड़ी पार्टी पर कज़्ज़ा कर लिया, जिसके पास कई दिग्गज नेता थे, और उसे बर्बाद कर दिया। यह आलोचना कांग्रेस के पूरे इतिहास पर नहीं है। बीजेपी के आलोचक भी कभी-कभी वाजपेयी के दौर की तारीफ़ करते हैं ताकि नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक, कांग्रेस के मणी शंकर अय्यर ने 2016 में %द इंडियन एज़्सप्रेस% के लिए बीमार वाजपेयी को एक भावुक खुला पत्र लिखा था, जिसका शीर्षक था प्लीज़ कम बैक, अटल जी। हालाँकि अय्यर हमेशा से आरएसएस और बीजेपी के आलोचक रहे हैं, फिर भी उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की कि मोदी ने किसी तरह वाजपेयी की विरासत को कमज़ोर किया है, जो क्ष्छ्वक्र से उनसे पहले प्रधानमंत्री थे। सरकार या नेता की इस तरह की आलोचना 1975-77 की इमरजेंसी के दौरान और उसके ठीक बाद साफ़ तौर पर देखी गई थी।

इतिहासकार रामचंद्र गुहा बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान पश्चिमी देशों की प्रेस में इंदिरा गांधी की ऐसी आलोचना हुई थी। गुहा अपनी किताब इंडिया आज़्टर गांधी में लिखते हैं, इमरजेंसी के दौरान नई दिल्ली आए द न्यूयॉर्क टाइज़्स के ए.एम. रोसेन्थल ने यह नतीजा निकाला कि अगर इंदिरा गांधी के शासनकाल में जवाहरलाल नेहरू ज़िंदा होते, तो वे सहयोगी के बजाय राजनीतिक विरोधी होते। रोसेन्थल के एक भारतीय दोस्त ने उस काल्पनिक स्थिति को कुछ इस तरह बयां किया था- %इंदिरा प्रधानमंत्री आवास में हैं और जवाहरलाल नेहरू जेल से उन्हें फिर से चिट्ठियां लिख रहे हैं। इमरजेंसी खत्म होने के ठीक बाद, किशोर कुमार ने %नसबंदी% फ़िल्म के लिए एक गाना गाया %बापू तेरे देश में कैसा अत्याचार%। यह फ़िल्म इमरजेंसी के दौरान जबरन की गई नसबंदी पर आधारित थी। इस गाने में महात्मा गांधी और नेहरू समेत कांग्रेस के आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का ज़िक्र करते हुए इमरजेंसी की आलोचना की गई थी। इसमें उसी तरीके का इस्तेमाल किया गया था जिसमें किसी नेता की आलोचना इसलिए की जाती है ज़्योंकि वह अपने ही परिवार और पार्टी की विरासत को कमज़ोर कर रहा होता है। इमरजेंसी के दौरान, सरकार की योजनाओं की तारीफ़ में गाना गाने से इनकार करने पर कुमार पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई थी।

स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार लाल किला पर गूंजेगा वंदे मातरम

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके की तैयारी कर रहा है। इस दौरान लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर पर पहली बार कुछ ऐतिहासिक होने जा रहा है, साथ ही युवा शक्ति पर खास ध्यान दिया जाएगा और प्रोटोकॉल का सज़्ती से पालन किया जाएगा। 15 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक बड़ा बदलाव करते हुए, लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया जाएगा। कार्यक्रम के नए क्रम के बारे में बताते हुए रक्षा सचिव आरके सिंह ने कहा कि यह पहली बार है जब हम इस क्रम का पालन कर रहे हैं। क्रम यह है कि वे (प्रधानमंत्री मोदी) प्राचीर पर पहुंचेंगे, फिर राष्ट्रगीत बजाया जाएगा और सभी लोग खड़े रहेंगे। इसके बाद, वे झंडा फहराएंगे और राष्ट्रगान बजाया जाएगा। इस खास मौके के जश्न में %युवा शक्ति% पर खास ज़ोर दिया जाएगा और छात्रों व युवा नागरिकों की कामयाबी और योगदान को सज़्मानित किया जाएगा। युवाओं की इनोवेशन की यह भावना राजधानी से कहीं आगे तक फैली हुई है। रक्षा सचिव सिंह ने साफ़ तौर पर कहा कि यह पहल पहले से ही तय थी।

जेपी नड्डा का राहुल गांधी पर पलटवार, देश को कर रहे गुमराह फैलाना चाहते हैं अराजकता

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र सरकार पर अपना हमला तेज़ करते हुए कहा कि विपक्ष गृह मंत्री की काल्पनिक बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता है। गांधी ने मांग की कि शाह साफ़ तौर पर बताएं कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे छात्रों पर लाठी, नुकीले डंडे और पैलेट गन के कथित इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी संसद और नैरेटिव, दोनों में ही रोज़ अपनी बात बदलते रहते हैं। उनका मकसद बातचीत करना नहीं, बल्कि अफ़रा-तफ़री फैलाना है। शुरुआत में, सत्र के शुरू होने पर उन्होंने ह्वश्वश्व्र पर चर्चा की मांग की थी। जब हम इसके लिए तैयार हो गए, तो उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा उठा दिया; इसके बाद, उन्होंने ज़ोर दिया कि गृह मंत्री जंतर-मंतर की घटना पर बयान दें। उनका इरादा सदन को काम करने से रोकना है।

वह नहीं चाहते कि सदन चले; इसीलिए वह पिछले 15 दिनों से कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और साथ ही जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा की मांग भी कर रहे हैं।

नड्डा ने कहा कि आज, जब यह तय हो गया कि जंतर-मंतर के मुद्दे पर चर्चा होगी, तो उन्होंने लोगों और देश को गुमराह करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि जंतर-मंतर पर गोलियां चली थीं, जबकि असल में ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी। गृह मंत्री हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारा रुख़ हमेशा से साफ़ रहा है- सदन को चलने दिया जाए। अगर सदन चलता है, तो हम हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इसका गवाह है। सरकार

इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि अगर अमित शाह ने खुद इस कार्रवाई का आदेश दिया था, तो उन्हें इसके लिए ज़िज़्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और अगर उन्हें इस फ़ैसले के बारे में पता नहीं था, तो यह उनकी अक्षमता होगी। गांधी ने आगे कहा कि दोनों ही स्थितियों में, गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी साफ़ किया कि विपक्ष अमित शाह से संसद में आकर किसी आम विषय पर बात करने के लिए नहीं कह रहा है।

संसद में गतिरोध: सरकार का प्रयास विफल, विपक्ष ने पीएम मोदी और अमित शाह से मांगा जवाब

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): सोमवार को लोकसभा ने विपक्ष के सांसदों की ज़बरदस्त नारेबाज़ी के बीच बिना किसी चर्चा के ट्रिज़्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026% पास कर दिया। राज्यसभा ने %टैज़्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026% को वॉइस वोट (मौखिक मतदान) के ज़रिए लौटा दिया। इससे पहले, उच्च सदन ने %बैंकर्स बुज़्स एविडेंस बिल, 2026% को वॉइस वोट से पास किया था। सोमवार को दोनों सदनों में कुछ रुकावटें आईं। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद, विपक्ष के विरोध और अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कुछ मिनटों बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कल 11 बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा में विरोध के बीच चार बिल पेश किए गए - ट्रिज़्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2026; मिनरल्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2026; केरल (ऑल्टरेशन ऑफ़ नेम) बिल, 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026। राज्यसभा ने कुछ देर के लिए कामकाज किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार ने सोमवार को छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर से कथित चढ़ावे की चोरी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की अपनी दोनों मांगों पर कायम है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये दोनों मांगें एक दूसरे से जुड़ी हैं तथा ''विपक्षी एकजुटता'' में दरार डालने के सरकार के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। सरकारी एजेंसियां

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष को उनका पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को (छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर) जवाब देना चाहिए। रीजीजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शज़्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार छात्रों के मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है।

रांची में छात्रों पर बल प्रयोग गलत, बातचीत ही समाधान-राहुल गांधी

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने झारखंड की राजधानी रांची में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है और झारखंड सरकार से आग्रह किया कि वह उनकी चिंताओं को सुने और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान करे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर प्रतिक्रिया देते हुए गांधी ने कहा कि अपनी बात रखने वालों के खिलाफ बल प्रयोग करने के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने का अधिकार है और समाधान केवल बातचीत से ही निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। इससे पहले दिन में, गांधी ने कहा कि झारखंड के छात्रों के लिए उनका संदेश स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा के इस्तेमाल का विरोध करती है। भौतिकशास्त्र

गांधी ने कहा कि हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे छात्रों पर हिंसा करने के खिलाफ हैं। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनकी शिकायतों का समाधान बातचीत के ज़रिए किया जाना चाहिए। उनके ये बयान छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों से निपटने के तरीके और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस बल के इस्तेमाल को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच आए हैं। रांची की घटना ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है, ज़्योंकि झारखंड सरकार कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (छ्वरूरू), वामपंथी दलों और राष्ट्रीय जनता दल (क्रछ्वष्ठ) के गठबंधन से चल रही है। बीजेपी ने झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं, खासकर इसलिए ज़्योंकि राहुल गांधी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान बल प्रयोग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

जेपीएससी-जेएसएसी छात्रों का उग्र प्रदर्शन: पुलिस ने किया आंसू गैस का इस्तेमाल

रांची १०/०८ (संवाददाता): रांची में जेपीएससी-जेएसएससी को लेकर छात्रों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है। %विधानसभा घेराव% मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच फिर से झड़प हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। रांची सिटी स्क्र पारस राणा ने कहा कि 90त्न छात्र शांतिपूर्ण हैं, लेकिन 10त्न किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अगर भीड़ में 700-1000 छात्र किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, यहां तक कि अपने प्रतिनिधियों की भी नहीं, और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी है - बैरिकेडिंग को धकेलते हुए और तीन पुलिसकर्मियों को कुचलते हुए आगे बढ़े - फिर भी पुलिसकर्मियों ने संयम बरता। उन्होंने पुलिस बल पर पत्थर भी फेंके। फिर भी, हमने बहुत कम समय के लिए ही सज़्ती दिखाई ज़्योंकि वे सभी

छात्र हैं। राणा ने कहा कि मैं सभी से शांति बनाए रखने और हिंसा न करने की अपील करता हूं। आपकी मांगें सरकार तक पहुंच रही हैं, आक्रामक न हों... हम छात्रों से अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और पुलिस पर पत्थर न फेंकें। जेपीएससी-जेएसएससीपरीक्षा की तैयारी कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों ने रांची में आंदोलन में शामिल सभी छात्रों से एकजुटता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि सोमवार को होने वाला विधानसभा मार्च शांतिपूर्ण रहे। रांची पुलिस आज के विधानसभा मार्च के लिए पूरी तरह तैयार है। स्क्र पारस राणा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को भरोसा दिलाया कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विधानसभा घेराव मार्च के दौरान, छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। %युवा% शज़्द को उल्टा करने पर वायु बनता है - और वायु को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आप इस विधानसभा मार्च में छात्रों का दर्द देख सकते हैं। मेरी 9 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी, मैं एज़्बुलेंस से यहाँ आया हूँ और स्ट्रेचर पर इस मार्च का हिस्सा बना हूँ। लेकिन यह सरकार हमारी आवाज़ दबा रही है और वॉटर कैनन व आँसू गैस के गोले इस्तेमाल कर रही है। यह निंदनीय है। सरकार डरी हुई है, यह कायर सरकार है। सरकार जब-जब डरती है, तब-तब पुलिस को आगे करती है... हम आगे बढ़ते रहेंगे। सरकार के साथ हमारी 3 दौर की बातचीत हुई है, उन्हें हमारी माँगें पूरी करनी चाहिए। अगर छात्रों की माँगें पूरी नहीं हुई, तो ष्टरूपद खतरे में पड़ जाएगा। सरकार हिल जाएगी, यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यह एक जन-आंदोलन बन गया है। %युवा% शज़्द को उल्टा करने पर %वायु% बनता है - और %वायु% को कोई नहीं रोक सकता। शरीर-रचनाविज्ञान

इससे पहले रांची पुलिस ने विधानसभा की ओर बढ़ रहे छ्वक्कस्ष्ट-छ्वस्स्ष्ट के प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (छ्वरुयरू) के विधायक जयराम कुमार महतो ने कहा कि विपक्षी पार्टियां ज़ाहिर है कि (प्रदर्शन को) थोड़ा समर्थन देंगी ही, ऐसा हर जगह होता है। लेकिन छात्र नाराज़ हैं। यह उनका प्रदर्शन है। अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं, तो वे प्रदर्शन नहीं करेंगे। मैं वहां (छात्रों के %विधानसभा घेराव% मार्च में) जा रहा हूं।

एज़्टिविस्ट देवेंद्र महतो विधानसभा की ओर छात्रों के विरोध मार्च में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया... इतने सारे लोग मार्च में शामिल हुए हैं।

विविध समाचार

शरद पवार के बाद स्टालिन भी आयेंगे पीएम मोदी के साथ ! भारत की चुनावी गणित बदलने की तैयारी लगभग पूरी

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): संसद के मानसून सत्र के अंतिम दौर में परिसीमन का मुद्दा एक बार फिर देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। शरद पवार गुट के सांसदों का सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मिलना महज महाराष्ट्र के सूखे, सिंचाई और क्षेत्रीय मांगों तक सीमित मुलाकात नहीं माना जा रहा। बैठक के बाद भले ही परिसीमन विधेयक पर प्रत्यक्ष चर्चा से इंकार किया गया हो, लेकिन इसके राजनीतिक मायने तलाशे जाने लगे हैं। खासकर इसलिए कि शरद पवार गुट के बारे में पहले से संकेत मिलते रहे हैं कि वह विधेयक के अंतिम स्वरूप और सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि जैसी शर्तों के आधार पर सरकार के प्रस्ताव का समर्थन कर सकता है। यहीं से मोदी सरकार की रणनीति का असली राजनीतिक खेल दिखाई देता है। सरकार के लिए परिसीमन महज एक विधेयक नहीं, बल्कि भविष्य के चुनावी प्रतिनिधित्व के ढांचे को प्रभावित करने वाला बड़ा संवैधानिक सवाल है। ऐसे में स्न्रष्टक्र संशोधन विधेयक को लेकर नरमी और परिसीमन पर व्यापक सहमति बनाने की कोशिशों को अलग-अलग घटनाओं की बजाय एक बड़े राजनीतिक समीकरण के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। स्रोतों के मुताबिक स्न्रष्टक्र विधेयक के मौजूदा स्वरूप का विरोध करने वाले दलों में छ्रस्न्थ और ह्रष्टक्र(स्क) शामिल हैं, जबकि दोनों को परिसीमन के मामले में संभावित संवाद-साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। मोदी सरकार का स्न्रष्टक्र विधेयक को आज के लोकसभा एजेंडे में नहीं रखना इसी रणनीतिक गणित को हवा देता है। रिपोर्टों में यह संभावना जताई गई है कि सरकार विवादित स्न्रष्टक्र प्रावधानों पर तत्काल टकराव से बचकर उन दलों के साथ राजनीतिक संवाद की गुंजाइश बनाए रखना चाहती है, जिनकी जरूरत परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक मुद्दे पर पड़ सकती है। हालांकि इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि सरकार विधेयक पर विस्तृत बहस चाहती हो। इसलिए इसे किसी पक्के राजनीतिक सौदे का प्रमाण मानना जल्दबाजी होगी।सबसे दिलचस्प मोर्चा छ्रस्न्थ का है। तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर छ्रस्न्थ लगातार दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व की चिंता उठा रही है। पार्टी सांसद कनिमोझी ने हाल में साफ कहा कि छ्रस्न्थ अपने पुराने रुख पर कायम है और तमिलनाडु के प्रतिनिधित्व की रक्षा की मांग

से पीछे नहीं हटी है। पार्टी ने यह भी कहा कि सरकार ने मौजूदा सत्र में विधेयक लाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और संशोधित मसौदा भी उसके सामने नहीं आया है। इसलिए यह कहना अभी सही नहीं होगा कि एमके स्टालिन सरकार के साथ आ गए हैं। लेकिन राजनीति में दरवाजे बंद होने और बातचीत की गुंजाइश बने रहने के बीच फर्क होता है। परिसीमन का प्रश्न दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति से जुड़ा होने के कारण छ्रस्न्थ का रुख निर्णायक महत्व रख सकता है। यदि केंद्र सरकार तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं का निराकरण करने वाला कोई ऐसा फार्मूला निकालती है, जिसमें प्रतिनिधित्व का संतुलन बना रहे, तो मौजूदा राजनीतिक विरोध में दरार की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। शरद पवार के मामले में भी तस्वीर इसी तरह सावधानी से पढ़नी होगी। प्रधानमंत्री से मुलाकात को लेकर राजनीतिक अटकलें तेज हुई हैं, लेकिन सुले ने स्पष्ट किया है कि विधेयक सामने आने के बाद ही पार्टी अपना रुख तय करेगी। यानी पवार खेमे का समर्थन अभी 'तय' नहीं, बल्कि संभावित समर्थन की राजनीतिक संभावना है। फिर भी भाजपा के लिए यह घटनाक्रम विपक्षी एकजुटता की परीक्षा जरूर है। राहुल गांधी और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच परिसीमन सहित गतिरोध पर हुई बातचीत को सरकार की ओर से 'अच्छी' बातचीत बताया गया और यह संदेश दिया गया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद संवाद के रास्ते बंद नहीं हैं।उधर, आज भी हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों का कामकाज प्रभावित हुआ, लेकिन सत्र के अंतिम दिनों में परिसीमन पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती दिख रही हैं। सरकार यदि इस सत्र में विधेयक के लिए पर्याप्त राजनीतिक सहमति जुटा पाती है, तो यह उसके लिए बड़ी संसदीय उपलज़्धि होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल होगा कि ज़्या वह ऐसी सहमति बना पाएगी जो उज़्र-दक्षिण प्रतिनिधित्व के विवाद को शांत कर सके? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने परिसीमन को केवल सदन की संज़्या का सवाल न रहने देकर उसे व्यापक राजनीतिक बातचीत का केंद्र बना दिया है।

शरद पवार गुट के साथ संवाद और छ्रस्न्थ की चिंताओं को साधने की कोशिश इसी बड़े समीकरण के संकेत हैं। यदि भाजपा इस गणित को साध लेती है, तो विपक्ष के लिए चुनौती केवल एक विधेयक का विरोध करना नहीं होगी, बल्कि बदलते राजनीतिक और चुनावी समीकरण का जवाब देना भी होगा। बहरहाल, फिलहाल सबसे बड़ा संदेश यही है कि मोदी सरकार ने अपने सामने खड़े राजनीतिक संकटों से निकलने की कला को अपनी रणनीति का हिस्सा बना लिया है। टकराव की बजाय संवाद, विरोधी खेमे में संभावित सहयोगियों की तलाश और बड़े मुद्दों पर सहमति का रास्ता बनाना उसकी राजनीति की खासियत बनती जा रही है। शरद पवार से संवाद हो या छ्रस्न्थ की चिंताओं को साधने की कोशिश, सरकार हर मोर्चे पर ऐसा राजनीतिक रास्ता तलाश रही है जिससे विपक्ष की एकजुटता कमजोर हो और उसके लिए बड़े फैसलों की राह आसान बने। परिसीमन पर यदि यह रणनीति सफल होती है, तो मोदी सरकार आने वाले वर्षों के चुनावी समीकरणों पर भी अपनी मजबूत राजनीतिक छाप छोड़ सकती है।

मैं 30 साल का और वे लोग 50 साल के..मायावती के भतीजे ने उज़्र प्रदेश के 2 लड़कों को ज़्यों कहा अंकल

लखनऊ १०/०८ (संवाददाता): उज़्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब छह महीने के करीब का वक्त शेष है। ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चली है और चुनावी रैलियों का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने भी अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कॉर्डिनेटर आकाश आनंद सवा दो साल बाद चुनावी मंच पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी नीत बीजेपी सरकार को तो निशाने पर लिया ही, इसके साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर भी चुटकी ले ली। हाथरस के सादाबाद में आकाश आनंद अपने पुराने आक्रमक चुनावी तेवर में नजर आए और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 10 साल से उनकी सरकार है, लेकिन केवल विज्ञापन के सहारे अपनी कमियों

को बीजेपी ने छुपाया है। जनता की टैज़्स की कमाई के पैसे से योगी सरकार और बीजेपी ने केवल अपना प्रचार किया है। भौगोलिकसंदर्भ

इसके साथ ही आकाश आनंद ने कहा कि मैं यहां पर बीजेपी की कमियां गिनाने नहीं आया हूं। मैं अपने लोगों की समस्याएं रखने आया हूं। भाजपा ने पिछले 10 सालों में न बहनों को सुरक्षित रख पाई, न नौकरी दे पाई और न शिक्षा दे पाई। अब हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार विफल रही है। कोई काम नहीं हुआ। 25 हजार से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए, जिनमें हमारे समाज के लोग पढ़ते हैं। मायावती जी ने काफी मेहनत की है, अपने समाज की आवाज उठाने के लिए। अपना वोट जरूर डालें, हाथी का बटन दबाएं। अगर किसी परिवार की बेटी या बहन गायब होती है, तो उस परिवार का दर्द कौन समझेगा? अगर मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी पुलिस के चक्कर लगाने पड़ें, तो आम आदमी न्याय की उज़्मीद किससे करे? किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसे न्याय मिलना चाहिए। आज सबसे बड़ा सवाल यही है, ज़्या यह एनकाउंटर की सरकार है या कानून के राज की सरकार? ज़्या यहां पुलिस का राज है, या गुंडों का राज?

आकाश आनंद ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए दोनों को %अंकल% कहकर संबोधित किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के %राहुल अंकल% भले ही बाबा साहब का नाम जपते हों, लेकिन उनकी सरकारों का हाल भी भाजपा जैसा ही है।

इसके बाद अखिलेश यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने साफ किया कि वे बेहद सज़्मान के साथ उन्हें %अंकल% कह रहे हैं। आकाश ने तर्क दिया कि अगर 30 साल का कोई युवा 50 साल के अखिलेश जी को %अंकल% नहीं कहेगा, तो आखिर ज़्या कहेगा!

छात्र आंदोलन पर विस्तृत चर्चा को तैयार सरकार, गृह मंत्री अमित शाह देंगे हर सवाल का जवाब

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): सोमवार को मॉनसून सत्र के आखिरी हज़्ते की शुरुआत के साथ ही संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने की कोशिश में, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि केंद्र सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में मीडिया को जानकारी देते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने पूरी और विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव दिया है, लेकिन विपक्ष को सदन की कार्यवाही चलने देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संसद में शाह का जवाब सुनना चाहिए और चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल साफ है कि वह छात्र आंदोलन

और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तृत चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष से मेरी बस यही बात है कि जब चर्चा और उसका जवाब हो रहा हो, तो विपक्ष को गृह मंत्री का बयान रोकने के लिए हंगामा नहीं करना चाहिए। उन्हें गृह मंत्री और सरकार का जवाब सुनना चाहिए। एक बार चर्चा शुरू हो जाए, तो हमें उस पर विस्तार से चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष ने संसद से शाह की गैर-मौजूदगी को लेकर बार-बार सरकार को घेरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता (स्रुशक्क) राहुल गांधी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री की गैर-मौजूदगी यह साबित करती है कि 20 जुलाई को हुई हिंसा के लिए वही जिज़्मेदार थे, जब %कॉकरोच जनता पार्टी% (ष्टछ्वक्क) के प्रदर्शनकारियों ने %चलो संसद% मार्च निकाला था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं देखा है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है और हमने अपनी अलग-अलग बैठकों में जो चर्चा की है, वह खास तौर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और बर्बरता पर गृह मंत्री के बयान के बारे में है। हमें इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि गृह मंत्री छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और बर्बरता पर बोलेंगे या नहीं; इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। सरकार ने इस बात पर भी कोई ठोस जवाब नहीं दिया है कि ज़्या वे अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन पर बहस करने के लिए तैयार हैं।

पूरे ढ्ढहृष्ठढ्ढ गठबंधन ने इस मामले में गांधी का समर्थन किया है और बार-बार संसद की कार्यवाही में बाधा डाली है। इससे पहले दिन में, विपक्षी सांसदों ने हाथों में तज़्तियां लेकर संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और शाह के खिलाफ नारे लगाए।

जंतर-मंतर पर छात्रों के लिए आवाज, झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर चुप्पी, वाह ज़्या दोगलापन है!

रांची १०/०८ (संवाददाता): झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और वह विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब किसी भाजपा शासित राज्य में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई होती है तो विपक्ष लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों की दुहाई देता है।

परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ रांची में हजारों प्रतियोगी अज़्यर्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी रहा। झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों ने एक के बाद एक कई पुलिस बैरिकेड तोड़े, जिसके बाद जगन्नाथपुर मंदिर के पास पुलिस ने पानी की बौछारें कीं और लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गये। सवाल यह है कि छात्रों के इस आंदोलन और पुलिस कार्रवाई पर वह विपक्ष आखिर चुप ज़्यों है, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर लगातार सवाल उठाता रहा है?

यह सवाल इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है ज़्योंकि

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है और वह विपक्षी दलों के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जब किसी भाजपा शासित राज्य में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई होती है तो विपक्ष लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और युवाओं के अधिकारों की दुहाई देता है। लेकिन जब उसी तरह की स्थिति विपक्ष शासित राज्य में पैदा होती है तो ज़्या वही मापदंड लागू नहीं होने चाहिए? यही नहीं, कल तक छात्रों के अधिकारों की आवाज उठाने का दावा कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं ने भी चुप्पी साध ली है जिससे उन पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में प्रदर्शन कर रहे अज़्यर्थी जेएसएससी-सीजीएल समेत विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, कुछ परीक्षाओं को रद्द करने और जेपीएससी-जेएसएससी में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच या राज्य से बाहर के उच्च न्यायालयों के सेवानिवृज़ न्यायाधीशों की समिति से जांच कराने की मांग पर अड़े हैं। सरकार का दावा है कि उसने प्रदर्शनकारियों की 98 प्रतिशत मांगें स्वीकार कर ली हैं। वहीं आंदोलनकारी कहते हैं कि जिन 13 परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी, उनमें से केवल तीन पर सरकार सहमत हुई है। यही मूल विवाद है और बातचीत के कई दौर के बावजूद गतिरोध समाप्त नहीं हो पाया है। हम आपको बता दें कि छात्रों के आंदोलन ने आज उस समय और ध्यान खींचा जब मुज़्यमंत्री हेमंत सोरेन का 51वां जन्मदिन भी था। करीब साढ़े 10 बजे शुरू हुए मार्च में प्रदर्शनकारी हाथों में तिरंगा और तज़्तियां लेकर विधानसभा की ओर बढ़े। एक पोस्टर पर मुज़्यमंत्री को लेकर लिखा था, छात्रों की समस्याएं मत देखो, छात्रों की आवाज मत सुनो और छात्रों के सवालों का जवाब मत दो। साथ ही आंदोलन का एक मानवीय पहलू भी है। नौ दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे जेएलकेएम नेता देवेंद्रनाथ महतो 10.5 किलोग्राम वजन घटने के बावजूद एंबुलेंस से मार्च में शामिल हुए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। आंदोलन की अगुवाई कर रहे जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच ने भी कथित असामाजिक तत्वों को आंदोलन में घुसने से रोकने के लिए करीब 500 स्वयंसेवक तैनात किए। वहीं पुलिस का कहना है कि वह संयम बरत रही है। पूरे चार किलोमीटर मार्ग पर 1,500 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए और निषेधाज्ञा भी लागू रही। आज रांची में जो कुछ हुआ उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बड़ा सवाल केवल यह नहीं है कि पुलिस ने लाठीचार्ज ज़्यों किया। सवाल यह भी है कि छात्रों की समस्याओं को लेकर राजनीतिक दलों की संवेदनशीलता सज़ा के साथ बदल ज़्यों जाती है? दिल्ली में छात्रों पर कार्रवाई हो तो लोकतंत्र खतरे में दिखाई देता है, लेकिन झारखंड में छात्रों पर पानी की बौछार और लाठीचार्ज हो तो वही आवाजें कमजोर ज़्यों पड़ जाती हैं? ज़्या छात्रों के अधिकार राजनीतिक सुविधा के अनुसार तय होंगे? ज़्या विपक्ष की जिज़्मेदारी केवल तब तक है, जब तक सज़ा में उसका प्रतिद्वंद्वी बैठा हो? भाजपा ने इसी आधार पर कांग्रेस और विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है। बहरहाल, यह साफ नजर आ रहा है कि झारखंड के युवाओं को राजनीतिक बयानबाजी नहीं, स्पष्ट जवाब चाहिए। परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और भर्ती प्रक्रिया में भरोसा बहाल करना सरकार की जिज़्मेदारी है। साथ ही विपक्ष की भी परीक्षा यही है कि वह सज़ा की राजनीति से ऊपर उठकर छात्रों के सवालों पर समान आवाज उठाता है या नहीं।

सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में कांवड़ियों पर बरसाए फूल, दिया भक्ति का संदेश

नयी दिल्ली १०/०८ (संवाददाता): मध्य प्रदेश के मुज़्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को जबलपुर में %संस्कार कांवड़ यात्रा 2026% में हिस्सा लिया, जो पवित्र श्रावण महीने का दूसरा सोमवार था। कार्यक्रम के दौरान, मुज़्यमंत्री यादव ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाकर उनका स्वागत किया और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं।ढ्ढह्ल से बात करते हुए यादव ने कहा कि आज जबलपुर में, जो माँ नर्मदा का शहर है, लाखों श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ को नर्मदा जल चढ़ाने के लिए कांवड़िए के तौर पर निकले हैं। मैं सभी को दिल से बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि सावन का पवित्र महीना सभी की मनोकामनाएं पूरी करे और उनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करे। यादव ने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं ने इस यात्रा

में हिस्सा लिया और भगवान शिव को चढ़ाने के लिए नर्मदा नदी से जल लेकर आए। इससे पहले उसी दिन, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी %संस्कार कांवड़ यात्रा% में हिस्सा लिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को यात्रा से जुड़े पर्यावरण का संदेश देने का एक मौका बताया; यह यात्रा प्रकृति को न्याय दिलाने और उसकी रक्षा करने की भावना के साथ आयोजित की जाती है। पटवारी ने कहा कि संस्कार कांवड़ यात्रा इस भावना के साथ निकाली जाती है कि हमें प्रकृति के साथ न्याय करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। हम पेड़-पौधों, पानी, जंगलों और ज़मीन की बात करते हैं। भगवान भोलेनाथ की दिव्य उपस्थिति पेड़-पौधों में भी झलकती है और यह यात्रा के ज़रिए ज़ाहिर होती है। जबलपुर संस्कृति और मूल्यों का शहर है, और अनगिनत कांवड़िये मध्य प्रदेश, देश और दुनिया में खुशी, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। वे दुनिया के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं और %वसुधैव कुटुंबकम%, प्यार और भाईचारे का संदेश देते हैं। जब मुझे इस कांवड़ यात्रा में शामिल होने का मौका मिला.

विविध समाचार

गौरव मेरा कंफर्ट जोन नहीं
डॉग वाले बयान पर
आकांक्षा चमोला ने तोड़ी चुप्पी

टेलीविजन अभिनेत्री और 'लॉकअप-2' कंटेस्टेंट रही आकांक्षा चमोला ने पति गौरव खन्ना को लेकर दिए गए विवादित बयान पर चुप्पी तोड़ी। अभिनेत्री ने बताया कि जिस तरह से उनके बयानों को तोड़कर दिखाया गया है, वैसा कुछ भी नहीं था। आकांक्षा चमोला ने शो से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, 'मैं चाहती थी कि शो के अंदर विजिटर के तौर पर मुझसे वो लोग मिलने आए, जिनके साथ मैं अपना कंफर्ट महसूस करती हूं जैसे कि मेरे माता-पिता या फिर डॉग आते तो मुझे अच्छा लगता, क्योंकि इनके साथ मैं अपना कंफर्ट महसूस करती हूं। गौरव भले ही मेरा पति है और अब हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं, लेकिन वो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। वो पता नहीं क्यों आया, शायद अपनी मर्जी से आया होगा।' दरअसल, शो के दौरान आकांक्षा चमोला के पति गौरव खन्ना उनसे मिलने के लिए आए थे, जिसके कुछ एपिसोड बाद अभिनेत्री ने बताया था कि शो के दौरान गौरव खन्ना की जगह कोई ऐसा मिलने आता, जिसके साथ वो अपनापन महसूस करती, भले उनका डॉग मिलने आता।

शो में एंट्री लेने से पहले आकांक्षा चमोला ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया था कि वह और गौरव खन्ना एक साल से अलग रह रहे हैं और तलाक लेने जा रहे हैं। इसके बाद श्रेया कालरा ने उनका दूसरा सीक्रेट रिवील कर दिया था कि वे बायसेक्सुअल हैं, जिसके बाद आकांक्षा चमोला ने ये बात स्वीकारी भी थी। साथ ही ये भी बताया था कि पति गौरव खन्ना को भी उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में पता था। रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए गए इस शो में शिल्पा शिंदे, श्रेया कालरा, आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, सुनीता आहूजा, राम कपूर, शिवांगी जोशी, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला, धीरज धूपर, माधुरी जैन ग्रोवर, रियाज अली और वरुण यादव उर्फ लैला जैसे पॉपुलर नाम थे, हालांकि कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने टॉप 3 की रेस में शिवांगी जोशी और योगेश रावत को हराकर इस सीजन की ट्रॉफी अपने नाम कर 1 करोड़ का इनाम भी अपने नाम किया।

टाइगर श्रॉफ के साथ एक्शन फिल्म बनाएंगे विक्की जैन, शुरू किया प्रोडक्शन हाउस

विक्की जैन ने प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है। उनके VJ Frames नाम से प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म में टाइगर श्रॉफ नजर आएंगे। इस एक्शन फ्रैंचाइजी के निर्देशन की जिम्मेदारी रेमो डिसूजा संभालेंगे। विक्की जैन चर्चित टीवी अभिनेत्री अंकिता लोखंडे के पति हैं। विक्की अब फिल्म निर्माता की कुर्सी पर बैठेंगे। अपने बैनर की पहली एक्शन फिल्म में उन्होंने टाइगर श्रॉफ को साइन किया है। उनके अलावा अभिषेक बनर्जी और एल्विश यादव भी नजर आएंगे।

शुरू हुई शूटिंग, टाइटल तय नहीं

अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले विक्की जैन पहली फिल्म एक्शन फ्रैंचाइजी बना रहे हैं। हालांकि, फिलहाल इसका टाइटल तय नहीं हुआ है। आज शनिवार से इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। अभिनेत्री और विक्की जैन की पत्नी अंकिता लोखंडे ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इसी के साथ प्रोडक्शन हाउस शुरू करने पर शुभकामनाएं भी दी हैं।

टाइगर श्रॉफ वर्क फ्रंट

टाइगर श्रॉफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें साजिद नाडियाडवाला की 'बागी 4' में देखा गया था। फिल्म बीते साल सितंबर में रिलीज हुई थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर यह सफलता हासिल नहीं कर पाई। वहीं, रेमो डिसूजा की बात करें तो उनके निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म अभिषेक बच्चन अभिनीत 'बी हैप्पी' थी।

नेटफ्लिक्स ओरिजिनल चुंबक में नजर आएंगी संदीपा धर
शेयर किया लेग-डे वॉर्म-अप रूटीन

मुंबई फिटनेस के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए मशहूर अभिनेत्री संदीपा धर ने हाल ही में अपने फैंस को लेग-डे वर्कआउट की तैयारी की एक झलक दिखाई है। अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपने लेग-डे से पहले अपनाई जाने वाली एक प्रभावी वॉर्म-अप टेक्निक दिखाई है, जो उनके वर्कआउट रूटीन का अहम हिस्सा है। गौरतलब है कि लेग-डे वर्कआउट में ताकत, लचीलापन और सहनशक्ति की जरूरत होती है। ऐसे में सही वॉर्म-अप मसल्स को एक्टिवेट करने और शरीर को कठिन एक्सरसाइज के लिए तैयार करने में मदद करता है। संदीपा का यह फिटनेस-फर्स्ट अप्रोच उनकी अनुशासित और नियमित लाइफस्टाइल को दर्शाता है। वर्कफ्रंट की बात करें तो संदीपा धर जल्द ही नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज 'चुंबक' में नजर आनेवाली हैं। इस एंसेम्बल कॉमेडी सीरीज में उनके साथ नीना गुप्ता, अर्जुन बिजलानी, सुमीत व्यास, हेली शाह और कई अन्य कलाकार दिखाई देंगे। मुंबई के बैकग्राउंड पर आधारित यह सीरीज 28 अगस्त 2026 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। एक ओर जहां संदीपा अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी ओर वह अपनी फिटनेस और वेलनेस को भी उतनी ही प्राथमिकता दे रही हैं। उनका यह संतुलन उनके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों के प्रति समर्पण को दर्शाता है।

'ललकारा' से क्यों हटे फरहान अख्तर? सामने आई वजह

बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर ने अपनी अपकमिंग स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'ललकारा' की कास्टिंग में बड़ा बदलाव किया है। फरहान अख्तर के इस प्रोजेक्ट से हटने के बाद अब एक्टर सिद्धांत गुप्ता इसमें शामिल हो गए हैं।

प्रोजेक्ट से क्यों हटे फरहान?

एक रिपोर्ट के मुताबिक, फरहान अख्तर ने फिल्म से इसलिए किनारा कर लिया क्योंकि इसकी शूटिंग का शेड्यूल संगीतकार आर.डी. बर्मन पर बन रही बायोपिक की शूटिंग से टकरा रहा था।

फरहान की जगह लेंगे सिद्धांत

अब 'ललकारा' में फरहान अख्तर की जगह सिद्धांत गुप्ता अदाकारी करेंगे। सिद्धांत को सीरीज 'जुबली' और 'फ्रीडम एट मिडनाइट' में एक्टिंग के लिए काफी तारीफ मिली है। उम्मीद है कि हाल के वर्षों की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जा रही इस फिल्म में एक्टर, आमिर खान के साथ एक अहम किरदार निभाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिद्धांत फिल्म में मुख्य किरदारों में से एक (पैरेलल लीड) निभाएंगे। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर हालिया सफलता के बाद उनके करियर में यह एक और बड़ा पड़ाव होगा। खबर है कि एक्टर ने रोल के लिए तैयारी शुरू कर दी है, हालांकि मेकर्स ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

किस पर आधारित है फिल्म

'ललकारा' क्रिकेटर लाला अमरनाथ की जिंदगी पर आधारित है, जो देश के लिए टेस्ट शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर थे। आमिर खान फिल्म में इस मशहूर खिलाड़ी का रोल निभाएंगे। फिल्म में आजादी से पहले और बाद के भारत की पृष्ठभूमि में मैदान के अंदर और बाहर उनके सफर को दिखाया जाएगा।

10 साल बाद लीड हीरो बनकर लौटेंगे इमरान खान

अभिनेता इमरान खान ने काफी वक्त से स्क्रीन से दूरी बना कर रखी थी। मगर अब वह बतौर लीड एक्टर दमदार वापसी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' से जुड़ी जानकारी साझा की।

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इमरान खान ने अपनी अगली फिल्म के बारे में काफी कुछ बताया। हॉलीवुड रिपोर्टर से बातचीत में इमरान ने कहा, 'मेरी फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' की शूटिंग पूरी हो चुकी है। यह फिलहाल पोस्ट-प्रोडक्शन में है और इस साल के अंत तक इसके रिलीज होने की उम्मीद है। यह एक एडल्ट रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जो मेरे जीवन के मौजूदा हालात दर्शाती है।'

इमरान खान आखिरी बार साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म 'कट्टी बट्टी' में बतौर लीड हीरो नजर आए थे। अब वे सीधे फिल्म 'अधूरे हम अधूरे तुम' में लीड रोल प्ले करेंगे। फिल्म के बारे में आगे एक्टर ने कहा, 'मैंने अभी-अभी एक बेहद प्रतिभाशाली युवा अभिनेत्री, गुरफतेह पीरजादा के साथ काम किया है। दरअसल, यह तो फिल्म है जिसे मुझे 10 साल बाद बनाना ही था।' बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया है।

इमरान खान का वर्कफ्रंट इमरान खान ने 2008 में रिलीज हुई 'जाने तू या जाने ना' से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा भी नजर आई थीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इमरान ने 'लक', 'आई हेट लव स्टोरीज', 'देल्ही बेली' और 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' जैसी कई हिट फिल्में दी थीं। इस साल जनवरी में इमरान ने अपने मामा आमिर खान के बैनर तले बनी फिल्म 'हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस' में कैमियो किया था।

मेरा बेटा वीर आर्मी में जाना चाहे तो खुशी होगी, मैं उसे रोकूंगा नहीं

कभी असल जिंदगी में सेना में जाने का ख्वाब देखने वाले ऐक्टर जिमी शेरगिल अपनी नई सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर में कारगिल युद्ध के हीरो विंग कमांडर बीएस धनोवा की भूमिका निभा रहे हैं। जिमी का मानना है कि देश के जवानों की बहादुरी की ये कहानियां युवा पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ताकि उन्हें अपने देश और जवानों पर गर्व हो और वो सैन्य सेवाओं को अपने करियर के तौर पर चुनें। यहां तक कि अगर उनका खुद का बेटा वीर भी अगर सेना में जाना चाहे तो उन्हें खुशी ही होगी। बकौल जिमी शेरगिल, 'ऑपरेशन सफेद सागर देश के जवानों की बहादुरी की सच्ची कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक वक्त पर जाकर ये बहादुरी खत्म हो जाएगी। जिस तरह की बहादुरी हमारे जवान, वो चाहे एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, नेवी हो, दिखाते हैं, उनके किस्से युवा पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है।'

ऑपरेशन सफेद सागर

देश के जवानों की बहादुरी की सच्ची कहानी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़नी बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक वक्त पर जाकर ये बहादुरी खत्म हो जाएगी। जिस तरह की बहादुरी हमारे जवान, वो चाहे एयरफोर्स हो, मिलिट्री हो, नेवी हो, दिखाते हैं, उनके किस्से युवा पीढ़ी तक पहुंचना बहुत जरूरी है।

90 पर्सेंट मार्क्स लाकर भी उस कट ऑफ के पार नहीं

जिमी आगे बताते हैं, 'जब हम स्कूल में थे, तब 99.9 पर्सेंट स्टूडेंट सेना में जाने की कोशिश करते थे। चूंकि उसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा होता था तो मेरे जैसे लोग 90 पर्सेंट मार्क्स लाकर भी उस कट ऑफ को पार नहीं कर पाते थे। इसलिए, मेरा तो सपना ही रह गया लेकिन अगर किसी में वो जुनून, वो जज्बा है, वो क्षमता है, आप हर तरीके से फिट हैं तो आपको पहली चॉइस निश्चित तौर पर आर्म्ड फोर्सेस रखनी चाहिए क्योंकि जो जिंदगी वहां पर है, वो और कहीं नहीं है। मैं 2001 से एयर बेस पर जाकर शूट कर रहा हूं, आर्मी एरिया में जा रहा हूं। वो इतनी कमाल की जगह है। जो सुकून, अनुशासन वहां देखने को मिलता है, वो कहीं नहीं है। वो एक अलग ही दुनिया है।'

हमें आपस में लड़ना बंद करना चाहिए

वहीं, विंग कमांडर बीएस धनोवा की भूमिका निभाने को लेकर जिमी ने कहा, 'रियल लाइफ हीरो असल में बड़े आम और सिंपल लोग होते हैं। वे जमीन से जुड़े हुए बेहद विनम्र लोग होते हैं, मगर वो जो काम करते हैं वो हीरोइक होता है। इसलिए, हमने भी शो में सिंपलिसिटी, विनम्रता आदि तो मेंटेन करने की पूरी कोशिश की है। हमारी कोशिश रही है कि हम कहीं भी फैले हुए न लगे।' वहीं, क्या जिमी देश के लिए खुद कुछ करने की चाह रखते हैं? इस सवाल पर उनका कहना था, 'मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें आपस में लड़ना बंद करना चाहिए। हम लोग आपस में टूटते जा रहे हैं। हमें टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तब बाहर की ताकतें आकर ऐसी चीजों का फायदा उठाती हैं। इसलिए, हम आपस में एकजुट होकर रहें, वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी।'

बेटा जो करना चाहे, मैं साथ दूंगा

जिमी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सैन्य सेवाओं को करियर चॉइस में सबसे ऊपर रखना चाहिए, तो क्या वे अपने बेटे वीर को भी यही सलाह देंगे? इस पर उन्होंने कहा, 'वीर अगर क्वॉलिफाई कर सकता है तो बिल्कुल। मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे बच्चे को जो भी करना है, मैं उसे कभी नहीं रोकूंगा। उनको अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो उसमें जाए। ऐसे ही, अगर वो आर्म्ड फोर्सेस में पहुंच सकते हैं, उनमें वो क्षमता है, बुद्धिमता है तो जरूर जाए।'

कलिंग समाचार

मंगलवार 11 अगस्त 2026

जेन जी को नहीं चाहिए माफी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बारह साल पहले जब सत्ता संभाली थी तो नेहरू जी की नकल करते हुए खुद को प्रधानमंत्री की जगह प्रधानसेवक बताया था। लेकिन उनका व्यवहार किसी राजा की तरह ही बना रहा, जो इस देश के नागरिकों को प्रजा की तरह देखता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं गुमराह बच्चों को माफ करता हूं। आप जानते हैं कि नरेन्द्र मोदी इन दिनों संसद की जगह इंस्टाग्राम पर ज्यादा नजर आ रहे हैं। उनकी जो नयी रील आई है, उसमें उन्होंने फिर से खुद को पीड़ित की तरह पेश करते हुए देश की नयी पीढ़ी को माफ करने का संदेश दिया है। माफी का यह फरमान मोदी के लिए अब बड़ी फांस बन गया है। और तमाम लोग इस पर उनके पुराने वीडियो निकाल कर बैठे हैं, जिसमें वो खुद अपशब्द कह रहे हैं या उन लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर फॉलो कर रहे हैं, जिन्होंने गालियों की राजनीति की। प्रधानमंत्री के इस माफ करने के फरमान पर अब सैकड़ों रील्स और मी स इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अगर भाजपा को लगता है कि वो दमनकारी हथकंडे यानी पुलिस का डर दिखाकर, अदालतों के चक्कर लगवाकर इन युवाओं को डराएगी, तो वो खुद को ही अंधेरे में रख रही है। मोदी ने तो कह दिया है कि हम नयी पीढ़ी को अदालतों के चक्कर नहीं लगवाना चाहते, उन्हें सही राह पर लाना चाहते हैं, तो इसका भी जवाब अब जेन जी दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी ताजा रील में कल्चरल शॉक यानी सांस्कृतिक तौर पर लगने वाले झटके की बात भी कही कि लड़कियां गाली दे रही हैं। इस एक वाक्य ने उनके मन में बैठे भेदभाव को सामने ला दिया। लड़के गाली दें तो उन्हें झटका नहीं लगता, लड़कियों की भाषा पर आपत्ति है। और सबसे पहली बात तो यही है कि मुद्दा गाली होना चाहिए या पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में हुए खिलवाड़ का होना चाहिए। जंतर-मंतर पर आंदोलन क्यों खड़ा हुआ, लाखों लोग क्यों चंद दिनों में एक ही मकसद के लिए जुट गए, किसलिए निहत्थी जनता ने बिना संसाधनों के सरकार के सामने प्रतिरोध करना शुरु किया, क्यों पुलिस के अत्याचार को हंसते-मुस्कुराते सह लिया, लेकिन अपने मकसद से पीछे लोग पीछे नहीं हटे, जिन युवाओं और बच्चों को अब तक गैरजि मेदार और अपने ही मोबाइल में गुम मानकर पिछली पीढ़ी के लोग डांटते-फटकारते रहते थे, उन लोगों ने कैसे देश को आंदोलन करने की एकदम नयी राह दिखा दी, इन सारे सवालों को गालियों के मुद्दे से दबाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। पिछले दस दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने चार-चार रील्स बनाकर खुद को जेन-ज़ी से जोड़ने की कोशिश की। पहली रील 23 जुलाई को रात बारह बजने में आठ मिनट कम पर यानी 11.52 पर आई। मोदी इतना तो जानते हैं कि आज के बच्चे सोने या जागने के लिए दिन-रात के मोहताज नहीं हैं। जब इनका मन करता है सोते हैं, जब मन करता है रात भर जाग कर काम करते हैं। खैर मोदी ने हैलो फ्रैंड्स कहकर नीट पेपर लीक पर सरकार ने क्या-क्या किया, यह सब बताया। लेकिन इस रील में अपने कैमरा एंगल पर मोदी खूब फंसे। फिर दूसरी रील उन्होंने 24 जुलाई की रात को बनाई, इस बार पहली रील पर मिले भारी रिस्पॉन्स और सुझावों के लिए युवाओं का आभार जताया था। जबकि हकीकत ये है कि 23 तारीख वाली रील पर उनका मजाक ज्यादा बना था। खैर 26 जुलाई को एक और रील मोदी की आई, उन्होंने बताया कि नंदन नीलेकणि अब परीक्षा सुधार का काम करेंगे, सब कुछ हाईटेक होगा। लेकिन पिछली दोनों रील्स की तरह इस बार भी जेन-ज़ी ने उनसे जुड़ने से इंकार किया। तो फिर मोदी की चौथी रील शुक्रवार रात को आ गई, जिसमें उन्होंने अपने लिए कहे अपशब्दों पर बात की और साथ ही मैं माफ करता हूं, जैसा राजशाही फरमान सुनाया। इस रील पर राहुल गांधी ने भी लिखा कि अपने बच्चों को खोने वाले माता-पिता के आंसू, उनका बिलखना- इससे बड़ा कोई दुन्ख नहीं होता... उसके बाद भी प्रधानमंत्री की ये हि मत है कि वो छात्रों को माफ़' करने की बात करते हैं। क्या वो एक भी शोकाकुल परिवार से मिले जिन्होंने अपने बच्चे को खोया है या उन लोगों से जिनकी जमा पूंजी, ज़िंदगी, वक्त और सपने सब पेपर लीक से छीन लिए गए? जवाब है नहीं!

विश्व मंच पर भारत की बदनामी कौन करा रहा है?

राजेंद्र शर्मा

अयातुल्ला खामनेई सिर्फ पड़ोसी मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं थे, वह एशिया में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु भी थे, जिसके चलते खुद भारत में भी शिया आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर तथा देश के दूसरे अनेक हिस्सों में भी, बड़ी सं या में लोग शोक जताने के लिए उमड़ पड़े थे। ये भावनाएं इसलिए और भी प्रबल थीं कि खामनेई की इजराइली-अमेरिकी हमले में लक्षित हत्या को जुल्म की ताकत के हाथों %शहादत% के रूप में देखा जा रहा था.

गजा के खिलाफ दो साल से लंबे अमेरिका-समर्थित इजराइली नरसंहार का दो-टूक विरोध करने की जगह, कभी हां और कभी ना से दोनों पक्षों को खुश रखने की कोशिश करने और वास्तव में, नरसंहार के शिकार और नरसंहार करने वाले, दोनों को एक ही पलड़े पर तोलने की कोशिश करने के जरिए, इजराइली-अमेरिकी नरसंहार की पीठ ही थपथपाने से भी प्रधानमंत्री मोदी को संतोष नहीं हुआ। ध्वस्त कराने के बाद गज़ा के पुनर्निर्माण के नाम पर पेश किए जा रहे, खुल्लमखुल्ला साम्राज्यवादी अचल संपत्ति प्रोजैक्ट को अंजाम देने के लिए, खुद ट्र प के नेतृत्व में गठित कथित पीस बोर्ड में बाकायदा शामिल होने न होने से लेकर, फिलिस्तीनी इलाकों में जबरन यहूदी बस्तियां बसाए जाने की निंदा के संयुक्त राष्ट्रर महासभा के प्रस्ताव पर एक बार फिर, मोदी का भारत कभी हां कभी ना के झूले पर झूलता रहा। और जब एपस्टीन फाइलों के बढ़ते खुलासों की बढ़ती गर्मी से बचने के लिए, ट्रंप-नेतन्याहू जोड़ी ने हैडलाइन बदलने के लिए ईरान के खिलाफ हमले की साफ तौर पर तैयारियां शुरू कर दीं, ऐन मौके पर प्रधानमंत्री मोदी को भारत के इजरायल के साथ खड़े होने का प्रदर्शन करने के लिए, इजरायल का दौरा करना जरूरी लगा।

और 28 फरवरी की दोपहर में, एक स्वतंत्र, संप्रभु तथा परंपरागत रूप भारत के मित्र देश, ईरान पर इजरायल-अमेरिका के संयुक्त हमले के बाद? एक स्वतंत्र देश पर और वहां %शासन बदलवाने% या रिजीम चेंज के घोषित इरादे से, तमाम अंतरराष्ट्रीय नियम-कायदों का उल्लंघन करते हुए, बिना किसी उकसावे के किए गए हमले के खिलाफ मोदी के भारत के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला—हमला करने वालों की निंदा को तो छोड़ ही दो, हमले की निंदा का भी एक भी शब्द। हां! विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से, आम तौर पर शांति की अपील और प्रभावित देशों में भारतीय नागरिकों से सावधानी तथा आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने का परामर्श जारी कराने की खाना-पूरी पर ही संतोष कर लिया गया।

लेकिन, मोदी के भारत को हमलावर और हमले के शिकार के बीच, इस कथित %तटस्थता% की मुद्रा से भी संतोष नहीं हुआ। अमेरिका-इजरायल ने हमले के पहले ही दिन, जब टार्गेटेड हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता तथा राष्ट्राध्यक्ष, अयातुल्ला खामनेई तथा कई सैन्य नेताओं की हत्या कर दी गयी और राष्ट्रपति ट्रंप ने इस %बड़ी कामयाबी% के लिए बाकायदा गाल बजाना जरूरी समझा, मोदी के नये भारत ने इस पर पूरी तरह से चुप्पी ही साध ली। यह इसके बावजूद था कि अयातुल्ला खामनेई सिर्फ पड़ोसी मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं थे, वह एशिया में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु भी थे, जिसके चलते खुद भारत में भी शिया आबादी वाले उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले कश्मीर तथा देश के दूसरे अनेक हिस्सों में भी, बड़ी सं या में लोग शोक जताने के लिए उमड़ पड़े थे। ये भावनाएं इसलिए और भी प्रबल थीं कि खामनेई की इजराइली-अमेरिकी हमले में लक्षित हत्या को जुल्म की ताकत के हाथों %शहादत% के रूप में देखा जा रहा था और आम तौर पर इस्लामी परंपरा में और खासतौर पर शिया परंपरा में, शहादत का मुकाम बहुत ऊंचा माना जाता है। हैरानी की बात नहीं है कि खामनेई की %शहादत% ने ईरानी जनता को जिस तरह अमेरिकी-इजराइली हमले के खिलाफ एकजुट किया है, उस तरह शायद खामनेई की मौजूदगी नहीं कर सकती थी। बहरहाल, प्राय֊ हर चर्चित व्यक्ति की मृत्यु या जन्म दिन पर संदेश देने के लिए वि यात, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने, इस पूरे घटनाक्रम पर एक शब्द तक कहना जरूरी नहीं समझा। ज़्यादा जानें चुनावी सर्वेक्षण उपकरण हिंदी भाषा पाठ्यक्रम मनोरंजन उद्योग रिपोर्ट ׸द्यह्यश ऋद्गड्डस्र - राजस्थान की अनोखी तालाब संस्कृति दूसरी ओर, इस युद्ध से जुड़े घटनाक्रम पर मोदी का भारत चुप ही नहीं बना रहा। बेशक, उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन एक प्रकार से यह स्पष्ट करने के लिए कि वह इस टकराव में किस की तरफ है। अमेरिकी-इजराइली हमले के जवाब में, जब ईरान ने इजरायल के अलावा अमेरिकी सैन्य ताकत के केंद्रों के तौर पर पश्चिम एशिया में कतर, कुवैत, जोर्डन, बहरीन, ओमान आदि में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों व अन्य ठिकानों को अपनी मिसाइलों तथा ड्रोनों से निशाना बनाया, इस क्रम में यूएई भी हमले की जद में आया था। नरेंद्र मोदी ने इस तीखे टकराव के बीच, यूएई पर हमले (जाहिर है कि ईरानी) को ही %कड़ी निंदा% के लायक समझा; उसके नुकसान को ही शोक जताने लायक समझा; उसके साथ एकजुटता जताने की जरूरत समझी! इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति, जायेद अल नहयान को विशेष रूप से टेलीफोन किया था और बाद में उनसे हुई बातचीत की जानकारी बाकायदा सार्वजनिक भी की गयी।

इस सारे घटनाक्रम का किंचित विस्तार से जिक्र हमने यह ध्यान दिलाने के लिए किया है कि अमेरिका-इजरायल जोड़ी की सामराजी युद्धोन्मादी मुहिम का पिछलग्गू बनाकर भारत को नरेंद्र मोदी ने उस मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां वह परोक्ष रूप से एक स्वतंत्र देश की (ईरान) की इस जोड़ी के अकारण हमले के खिलाफ बचाव की कार्रवाइयों की निंदा के जरिए, इस सामराजी मुहिम का ही समर्थन कर रहा है। याद रहे कि यह आक्रांता और हमले के शिकार, दोनों के बीच %बराबरी% के पाखंड से नीचे गिरने का मामला है। यहां से आक्रांता का प्रत्यक्ष रूप से साथ देना, एक कदम ही दूर रह जाता है। इसमें से भी आधा कदम तो मोदी राज ने, सिर्फ और सिर्फ यूएई पर हमले को निंदनीय बताने के जरिए उठा भी लिया है। ज़्यादा जानें युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम करियर मार्गदर्शन सेवा राजनीतिक विश्लेषण रिपोर्ट कहने की जरूरत नहीं है कि यह साम्रज्यवादविरोधी स्वतंत्रता संघर्ष से निकली, भारत की साम्राज्यवाद के सामने स्वतंत्र नीति और साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रही दुनिया के साथ एकजुटता की समूची नीति के ही त्यागे जाने का मामला नहीं है, जिसे मोदी राज के बारह वर्षों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन से पूरी तरह से मुंह मोड़े जाने ने पहले ही निर्णायक बिंदु पर पहुंचा दिया था। लेकिन, साम्राज्यवादविरोधी स्वतंत्रता संघर्ष से न सिर्फ दूर रहे बल्कि उसकी जड़ें काटने में ही जुटे रहे, आरएसएसस के राजनीतिक मोर्चे के रूप में, भाजपा और उसकी सरकार से और उ मीद भी क्या की जा सकती थी। लेकिन, यह तो और आगे बढ़कर, स्वतंत्र विदेश नीति के ही पलटे जाने और विकासशील दुनिया के खिलाफ साम्राज्यवादी हुकुमशाही के खेमे के साथ जा मिलने का मामला है। जाहिर है कि यह सब करते-कराते हुए, जब-तब विकासशील दुनिया या ग्लोबल साउथ का मुखिया होने के अपने मुंह से खुद ही दावे करने से, मोदी के भारत को प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। उलटे सच्चाई यह है कि न सिर्फ विकासशील दुनिया ने मोदी के भारत को अपना मानना बंद कर दिया, जिसका पता पर्यावरण से लेकर विश्व व्यापार तक, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वार्ताओं में लगातार मिलता रहा है बल्कि एक दुरंगे चरित्र के रूप में मोदी का भारत बदनाम हो रहा है। पहले गज़ा और अब ईरान पर अमेरिकी-इजराइली हमला, भारत की बदनामी के बड़े मौके बन गए हैं। विश्व एआई समिट के दौरान दो-दर्जन युवाओं के बनियान/टीशर्ट में प्रदर्शन पर तो दुनिया की शायद ही कोई नजर पड़ी हो, पर स्वतंत्र भारत की स मानित विदेश नीति और उसके बुनियादी मूल्यों से मोदी राज की यह पल्टी जरूर, आम तौर पर दुनिया भर में और खासतौर पर विकासशील दुनिया में भारत का नाम बदनाम करा रही है।

कम से कम ट्रंप के राज के एक साल से ज्यादा में यह सब करने का भी भारत को जो नतीजा मिला है, इसी को दिखाता है। यह कोई संयोग ही नहीं है कि ट्रंप निजाम ने, भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ थोपा था और बाद में उसी टैरिफ को हथियार बनाकर, उसने भारत पर एक ऐसा असमानतापूर्ण व्यापार समझौता थोप दिया है, जो न सिर्फ भारत के अपने आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने वाला समझौता है बल्कि एक ऐसा समझौता भी है जो इस असमानता के साथ, अमेरिका की मर्जी की नीतियों पर चलने की शर्तों का योग करता है। यह भारत की संप्रभुता के गिरवी रखे जाने को संस्थागत रूप देने वाले समझौतों का रास्ता है। इस तरह, तथाकथित व्यावहारिकता के तर्क से वास्तव में भारत को अपनी स्वतंत्रता तथा संप्रभुता में कतरब्यौंत को स्वीकार करने के ही रास्ते पर धकेला जा रहा है। क्या यह एक स्वतंत्र देश के लिए बदनामी का ही रास्ता नहीं है। आखिर में एक बात और। अब जब सारी दुनिया में, बाल यौन उत्पीड़क दरिंदे एपस्टीन की फाइलों के खुलासों के असर से इस्तीफों से लेकर गिर तारियां तक हो रही हैं और तरह-तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, भारत में मोदी सरकार का रुख हरदीप पुरी से लेकर, अनिल अंबानी तक को नाम आने के बावजूद, एक प्रकार से क्लीन चिट देने का ही नजर आता है। क्या एक दरिंदे के साथ संपर्कों का इस तरह सामान्य बनाया जाना, दुनिया भर में भारत की बदनामी नहीं करा रहा है?

सीबीआई की साख पूरी तरह खत्म

के रवींद्रन

भौगोलिक संदर्भ भाजपा नेताओं ने बदले की कार्रवाई के आरोपों को लगातार खारिज किया है। फिर भी, जांच में गलत हथकंडे अपनाने के आधार पर किसी बड़े स्तर के मुकदमे का खत्म होना सत्ता के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक है। बड़ी चिंता संस्थागत है। सीबीआई की वैधता सिर्फ सज़ा पर ही नहीं, बल्कि जनता के इस भरोसे पर भी निर्भर करती है कि वह स्वतंत्र रूप से काम करती है और संवैधानिक नागरिक सुरक्षा उपायों का स मान करती है।

अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य के खिलाफ दिल्ली आबकारी नीति मुकदमे को खारिज करने के एक सत्र न्यायालय के फैसले से एक राजनीतिक और संस्थागत महत्व की निर्णायक चर्चा शुरू हो गयी है, जो एक मुकदमे की किस्मत से कहीं आगे की बात है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का प्रक्रियात्मक उल्लंघन, उसकी सुनी-सुनाई बातों पर निर्भरता और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की अनदेखी के लिए तीखी आलोचना करके, राउज एवेन्यू की अदालत ने न सिर्फ आरोपियों को बरी किया है बल्कि इसने भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की साख पर भी एक लंबा साया डाल दिया है।

महीनों तक यह आबकारी मुकदमा राजनीतिक बहस में छाया रहा है। दिल्ली की शराब नीति बनाने और उसे लागू करने में कथित गड़बड़ियों पर केंद्रित आरोपों को आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर प्रणालीगत भ्रष्टाचार के सुबूत के तौर पर पेश किया गया। उस समय के मु यमंत्री केजरीवाल और उनके उप-मु यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिर तार किया गया, उनसे बहुत पूछताछ की गई और राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें निजी फायदे के लिए बनाई गई नीति के वास्तुकार के तौर पर पेश किया। केजरीवाल भारत के पहले मु यमंत्री बने जिन्हें पद पर रहते हुए गिर तार किया गया। मोदी सरकार ने इस मामले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कदम बताया, जो शून्य सहनशीलता की उनकी गढ़ी एक बड़ी कहानी का हिस्सा था और बाद के चुनावों में भी उसने इसका पूरा इस्तेमाल किया।

अदालत द्वारा आरोप को ही खारिज से उस कहानी में रुकावट आती है। अपने आदेश में, न्यायाधीश ने जांच के तरीके में गंभीर कमियों को रेखांकित किया, और उन नाकामियों की ओर इशारा किया जो आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल पर हमला करती हैं। अदालत का यह निष्कर्ष कि संवैधानिक सिद्धांतों से समझौता किया गया और अभियोजन पक्ष ने बिना पुष्टि वाले बयानों पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, मामले की बुनियाद को ही कमजोर करता है। अदालत शायद ही कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो जांच की ईमानदारी पर सीधे सवाल उठाती हो। जब वे ऐसा करते हैं, तो इसके नतीजे तुरंत की कार्रवाई से कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं।

सीबीआई लंबे समय से राजनीतिक प्रभाव के प्रति स्वयं के कमज़ोर होने की धारणा से जूझ रही है। एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने कोयला आवंटन मामले की सुनवाई के दौरान इसे %पिंजरे में बंद तोता जो अपने मालिक की आवाज़ में बोल रहा है% कहा था। यह कहावत संस्थागत गुलामी के आशुलिपि के तौर पर लोगों की जुबान पर चढ़ गई। एक के बाद एक सरकारों ने एजेंसी की स्वायत्तता पर ज़ोर दिया है, फिर भी सभी राजनीतिक सरकारों में चुनिंदे मामलों में ज्यादा जोश दिखाने के आरोप लगते रहे हैं। दिल्ली के आबकारी मुकदमे के खारिज होने से यह सोच और पक्की हो सकती है कि सीबीआई की स्थिति में बहुत कम बदलाव हुआ है। भौगोलिक संदर्भ केजरीवाल का जवाब अपनी खासियत के हिसाब से आक्रामक था। उन्होंने आबकारी मामले में अभियोजन को आज़ाद भारत की %सबसे बड़ी राजनीतिक साज़िश% बताया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इसे अंजाम देने का आरोप लगाया। ऐसी बातें राजनीतिक रूप से आवेशित होती हैं, फिर भी अदालत की फटकार इसे और हवा देती है। जब कोई जांच प्रक्रिया की कमियों के कारण न्यायिक विचारण में फेल हो जाती है, तो राजनीतिक मतलब निकालने की गुंजाइश बढ़ जाती है। भाजपा नेताओं ने बदले की कार्रवाई के आरोपों को लगातार खारिज किया है। फिर भी, जांच में गलत हथकंडे अपनाने के आधार पर किसी बड़े स्तर के मुकदमे का खत्म होना सत्ता के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक है।

सीबीआई की वैधता सिर्फ सज़ा पर ही नहीं, बल्कि जनता के इस भरोसे पर भी निर्भर करती है कि वह स्वतंत्र रूप से काम करती है और संवैधानिक नागरिक सुरक्षा उपायों का स मान करती है। अगर अदालत को पता चलता है कि सही प्रक्रिया से समझौता किया गया है, तो एजेंसी की साख पर असर पड़ता है, चाहे राजनीतिक संदर्भ कुछ भी हो। आबकारी मुकदमे में निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब राजनीतिक विवादों में केन्द्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल बढ़ गया था। सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सीबीआई और आयकर अधिकारियों पर गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी, जिसने भ्रष्टाचार विरोधी सक्रियता पर अपना ब्रांड बनाया था, उसके लिए अदालत का आदेश यह तर्क देने का मौका देता है कि वह गलत काम करने वाली नहीं बल्कि शिकार पार्टी थी। केजरीवाल ने मोदी को दिल्ली में चुनाव कराने की चुनौती दी है। यह आ यान चुनावी फायदे में बदलेगा या नहीं, यह मतदाताओं की सोच पर निर्भर करेगा, लेकिन तुरंत मिलने वाले फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषण सेवा लोगों की याददाश्त फैसले से उतनी ही बनती है जितनी कि लक्षणा-व्यंजना से। सर्वोच्च न्यायालय की %पिंजरे में बंद तोता% वाली टिप्पणी स्वायत्तता से समझौता कर लेने का बिंब बन गई। राउज़ एवेन्यू की अदालत की फटकार से उस आ यान में एक और अध्याय जुड़ने का खतरा है। भरोसा वापस लाने के लिए सिर्फ सार्वजनिक बयानों से ज़्यादा की ज़रूरत होगी। इसके लिए कानून का साफ़ तौर पर पालन, गलतियों के लिए अंदरूनी जवाबदेही और ऐसे मामलों का लगातार रिकॉर्ड चाहिए होगा जो न्यायिक जांच में टिके रहें। ज़्यादा जानें करियर मार्गदर्शन सेवा भारतीय इतिहास पुस्तकें समाचार पत्र विज्ञापन केजरीवाल का एक बड़ी राजनीतिक साज़िश का आरोप उनके समर्थकों और विपक्ष के कुछ हिस्सों को पसंद आ सकता है। सरकार इसे पार्टी की बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात कहकर खारिज कर देगी। इन दोनों स्थितियों के बीच न्यायपालिका है, जिसका काम न तो राजनीतिक दावों को सही ठहराना है और न ही कहानियों पर फैसला सुनाना है, बल्कि सुबूतों और प्रक्रिया की जांच करना है। इस मामले में, जांच की आलोचना में जांच का आकलन साफ़ रहा है। भौगोलिक संदर्भ यह एक ऐसा मुकदमा है जो नाटकीय गिर तारी से शुरू होता है और प्रक्रिया की कमियों के कारण बर्खास्तगी पर खत्म होता है, और अपना निशान छोड़ जाता है। यह न केवल इसमें शामिल लोगों को बल्कि उन संस्थाओं को भी प्रभावित करेगा जिन्हें कानून का राज बनाए रखने का काम सौंपा गया है।

विविध समाचार

एनएच–5 बंद, कई वाहन क्षतिग्रस्त, सड़कों पर लंबा जाम, हिमाचल के किन्नौर में भारी बारिश से तबाही

शिमला। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने रफ्तार पकड़ते ही तबाही मचानी शुरू कर दी है। जनजातीय जिला किन्नौर में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने राष्ट्रीय उच्च मार्ग–5 (एनएच–5) को पूरी तरह बंद कर दिया। वहीं लाहौल–स्पीति में उफनते जाहलमा नाले के कारण एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए बैकहो लोडर का सहारा लेना पड़ा।

किन्नौर के चोलिंग क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ अपने साथ भारी मात्रा में मलबा और दलदल लेकर आई, जिससे एनएच–5 पूरी तरह अवरुद्ध हो गया।

सड़क पर चल रहे कई वाहन मलबे में फंस गए। हालांकि, राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और सभी लोग सुरक्षित हैं।

घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। उपायुक्त (डीसी) डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि चोलिंग के पास सड़क से मलबा हटाने और फंसे वाहनों को निकालने के लिए भारी मशीनरी तैनात कर दी गई है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए बहाल करने में जुटी हैं।

उधर, लाहौल–स्पीति जिले में जाहलमा नाले में आई बाढ़ के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नाले पर बना पुल पहले ही क्षतिग्रस्त था और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा बनाई गई अस्थायी पुलिया भी तेज बहाव में बह गई। इसके चलते उदयपुर उपमंडल और पांगी घाटी का संपर्क प्रभावित हो गया। इसी बीच उदयपुर उपमंडल के शेनुर गांव की रहने वाली शांति देवी को सीने में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ होने पर कुल्लू रेफर किया गया।

जब एंबुलेंस जाहलमा नाले के पास पहुंची तो तेज बहाव के कारण आगे बढ़ना संभव नहीं था। ऐसे में बीआरओ और पुलिस के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए मरीज को स्ट्रेचर सहित बैकहो लोडर की मदद से उफनता नाला पार कराया। दूसरी ओर पहुंचने के बाद उन्हें एंबुलेंस के जरिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू भेजा गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। बीआरओ ने गुरुवार सुबह नाले पर अस्थायी पुल बनाकर यातायात आंशिक रूप से बहाल कर दिया। उल्लेखनीय है कि मई में भूस्खलन के कारण जाहलमा पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद नए पुल का निर्माण कार्य जारी है। स्थानीय विधायक अनुराधा राणा ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के अंत तक नया पुल तैयार हो जाएगा।

शिमला में पोलियो अभियान के पहले दिन 50 हजार से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलायी गयी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन पांच वर्ष से कम उम्र के कुल 50,454 बच्चों को पोलियो रोधी खुराक (ओपीवी) पिलायी गयी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, जिले भर में दवा पिलाने के लिये पल्स पोलियो के 704 बूथ बनाये गये थे। इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ–साथ अन्य सरकारी विभागों, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनता ने बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यटकों के बच्चों की सुविधा के लिए शोघी पुलिस बैरियर पर एक विशेष ओपीवी बूथ बनाया गया था। यहाँ पर्यटकों को ले जाने वाली बसों और अन्य वाहनों को रोककर बच्चों को पोलियो की खुराक दी गयी। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने लोक गीतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दीं, जिन्हें पर्यटकों ने काफी सराहा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. यशपाल रांटा ने बताया कि चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों, स्वयंसेवकों, पुलिस और स्थानीय निकायों ने मिलकर अभियान को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि पहले दिन मिली अच्छी प्रतिक्रिया कर्मचारियों के आपसी तालमेल और माता–पिता में बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। जिले में सबसे अधिक 8,166 बच्चों को माशोबरा स्वास्थ्य ब्लॉक में पोलियो की खुराक दी गई। इसके बाद नेरवा में 7,771, शिमला शहरी में 6,886, कोटखाई में 5,426, मटियाना में 5,166, रामपुर में 5,014, टिकर में 3,773, चिड़गांव में 3,130, कुमारसैन में 2,065, सुन्नी में 1,928 और नानखड़ी में 1,129 बच्चों को दवा पिलायी गयी। डॉ. रांटा ने बताया कि यह अभियान 29 और 30 जून को भी जारी रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य टीमें घर–घर जाकर उन बच्चों को पोलियों की खुराक पिलाएंगी जो पहले दिन बूथ पर नहीं पहुंच पाए थे। उन्होंने माता–पिता से स्वास्थ्य टीमों का सहयोग करने की अपील की है ताकि देश को पोलियो मुक्त बनाए रखा जा सके।

सीमावर्ती डिफेंस डैम विवाद : राज्यपाल कटारिया ने लिया संज्ञान, गृह व रक्षा मंत्रियों से करेंगे चर्चा

चंडीगढ। फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों में प्रस्तावित डिफेंस डैम के निर्माण का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन ने अब राजभवन तक दस्तक दे दी है। पिछले 18 दिनों से जारी आंदोलन के बीच फाजिल्का के युवा सामाजिक कार्यकर्ता करण गिल्होत्रा की पहल पर 'बन्न रोको चढ़दी कला संघर्ष मोर्चा' के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से चंडीगढ़ स्थित राजभवन में मुलाकात कर ज्ञापन सौंप अपनी मांगें रखीं। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि प्रस्तावित डिफेंस डैम से सीमावर्ती गांवों के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि इससे कई गांव बारिशों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैंयकिसानों का कहना है राज्यपाल महोदय खुद्द इलाके का दौरा कर लें ताकि उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाजा हो सके और किसानों का कहना है कि परियोजना से होने वाले नुकसान को देखते हुए इसकी मौजूदा रूपरेखा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और प्रभावित ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान किया जाए। प्रतिनिधिमंडल में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता परमजीत सिंह नूरशाह, हरीश नड्डा, कुलवंत सिंह, महल सिंह, सुखदेव सिंह, धीरा बराड़, साहिल कंबोज, पुरुषोत्तम सिंह, सुखदेव सिंह राणा, शाम लाल और बीरबल सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।

होशियारपुर निगम चुनावों और आगामी विधान सभा चुनावों में सरकार की कारगुजारी को देखकर मतदान करे जनता : खन्ना

होशियारपुर। पूर्व सांसद अविनाश राय खन्ना ने जनता की समस्याओं को सुनने के लिए खुले दरबार का आयोजन किया। इस मौके खन्ना ने कहा कि बीते 5 वर्षों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी नाकामियों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। खन्ना ने कहा कि अपराध और नशों पर काबू पाना तो दूर की बात है, आप सरकार के राज में अपराध की दर पंजाब में बहुत बढ़ चुकी है। पंजाब की जवानी नशों के चंगुल में बुरी तरह फंसती जा रही है। खन्ना ने कहा की जब जनता को आम आदमी पार्टी की धांधलियों का ज्ञान हुआ तो अब पंजाब की महिलाशक्ति को भ्रमित करने के लिए भगवंत मान ने दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए नया पैंतरा खेलने का मन बनाया है। बीते 5 वर्षों में भगवंत मान ने पंजाब की जनता से किये हुए वाडे पूरे नहीं किये परन्तु ठीक 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले उन्होंने महिला शक्ति को हजार और पंद्रह सौ रूपए प्रतिमाह देने की घोषणा कर दी परन्तु पंजाब के मतदाताओं को यह सोचना होगा कि बीते 5 वर्षों में मुख्यमंत्री भगवंत मां को महिलाओं से किये हुए वादे की याद क्यों नहीं आयी और यदि मुख्यमंत्री दिल से महिलाओं को यह लाभ देना चाहते हैं तो वे हर महिला को बीते 5 वर्ष के पैसे उनके कहते में दें और इस लाभ में देरी के लिए मातृ शक्ति से माफी मांगें । पंजाब की मातृशक्ति सूझवान है और दूरदर्शी सोच रखती है । खन्ना ने कहा की अपने वादों से फिरने वाई आप सरकार अब चुनावों के वक्त जो लाभ जनता को देने का दिखावा कर रही है।

पाकिस्तान में 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब का ध्वस्तीकरण हिंदू–सिख आस्था पर सुनियोजित और कायराना हमला : तरुण चुग

चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने पाकिस्तान के फारूकाबाद (मंडी चुहरकाना) में 125 वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को बुलडोजर से ध्वस्त किए जाने की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि यह केवल एक इमारत का गिरना नहीं, बल्कि समूचे हिंदू–सिख समाज की आस्था, इतिहास और विरासत पर सुनियोजित हमला है। चुग ने कहा कि यह गुरुद्वारा साहिब सिंह सभा आंदोलन की जीवित धरोहर था और प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े पवित्र गुरुद्वारा सच्चा सौदा साहिब के निकट स्थित था। जिस धरती को गुरु साहिब की चरण–छोह प्राप्त है, उसी धरती पर बुलडोजर चलाकर पाकिस्तान ने अपना हिंदू–सिख विरोधी जहरीला चेहरा पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। चुग ने कहा कि इस ध्वस्तीकरण में पाकिस्तान सरकार और प्रशासन की खुली मिलीभगत है। स्थानीय व्यवसायी ने बिना अनिवार्य NOC लिए रातों–रात गुरुद्वारा साहिब को गिरा दिया और हिंदू–सिख समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद ही सरकार की नींद खुली। जिस भवन को पाकिस्तान सरकार ने स्वयं "ऐतिहासिक स्मारक" घोषित कर उसके ध्वस्तीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था, उसी भवन को दिनदहाड़े भू–माफिया ने मिट्टी में मिला दिया। चुग ने कहा कि यह प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि हिंदू–सिख विरोधी पाकिस्तानी हुकूमत का प्रशासनिक संरक्षण है कृ भू–माफिया वहां सरकार की गोद में बैठकर धार्मिक विरासत को निगल रहा है। चुग ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं, बल्कि पाकिस्तान का घिनौना पैटर्न है। इसी जून महीने में खैबर पख्तूनख्वा के मरदान में गुरुद्वारा साहिब की सेवा करने वाले सेवादार दंपती कृ जगन्नाथ और आशा वंती कृ की निर्मम हत्या कर दी गई। गुरुद्वारा कोहरियाँ (लाहौर), गुरुद्वारा श्री सिंह सभा (क्वेटा), टेरी का श्री परमहंस दयाल मंदिर, ल्यारी का 200 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर कृ सूची अंतहीन है। चुग ने कहा कि ये "पेवसंजमक पदबपकमदजे" नहीं, बल्कि हिंदू–सिख समेत ध ार्मिक अल्पसंख्यकों के व्यवस्थित सफाये की श्रृंखला है, जिसे कट्टरपंथी पाकिस्तानी हुकूमत का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। चुग ने कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 1947 में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 20–23ः थी, जो आज घटकर मात्र 3.5 प्रतिशत रह गई है। कहाँ गए वे करोड़ों हिंदू, सिख और ईसाई? जबरन धर्मांतरण, हत्याएं और पलायन कृ यही पाकिस्तान का 'अल्पसंख्यक मॉडल' है। चुग ने कहा कि 1950 के नेहरू–लियाकत समझौते में पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा स्थलों की सुरक्षा और जीवन–संपत्ति की रक्षा की गारंटी दी थी, लेकिन 76 वर्षों में पाकिस्तान ने इस समझौते की हर पंक्ति को रौंदा है। भारत ने अपने संविधान से अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, जबकि पाकिस्तान ने उन्हें बुलडोजर, भीड़ और भू–माफिया दिए। चुग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हिंदू–सिख आस्था के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। विदेश मंत्रालय ने इस ध्वस्तीकरण को "भ्पहीसल क्मचसवतंइसम" और "ज्तहमजमक ।बज वि टंदकंसपेउ" करार देते हुए पाकिस्तान से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई, गुरुद्वारा साहिब के शीघ्र पुनर्निर्माण और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की दो टूक मांग की है। भारत ने म्ज्ठ (इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड) की निष्क्रियता पर भी सीधा सवाल उठाया है, जिसे विभाजन के बाद हिंदू–सिख संपत्तियों की देखरेख के लिए ही बनाया गया था, लेकिन जो आज भू–माफिया का दलाल बनकर रह गया है। चुग ने उन नेताओं पर तीखा प्रहार किया जिन्होंने कल ही पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए मोहब्बत भरा खत लिखा। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तान की पीठ थपथपाने के लिए ये नेता कलम उठाते हैं, उसी पाकिस्तान में गुरुद्वारा साहिब का मलबा आज इनसे सवाल पूछ रहा है कृ क्या आपकी मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए है, वहां सिसकते हिंदू–सिख भाई–बहनों के लिए नहीं? चुग ने कहा कि जो नेता अपनी ही सेना से सबूत मांगते हैं और पाकिस्तान के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं, वे आज देश को बताएं कि हिंदू–सिख अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का यह अत्याचार उन्हें दिखता है या नहीं। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब की एक–एक ईंट इन क्लीन चिट बांटने वालों के दोहरे चरित्र की गवाही दे रही है। चुग ने कहा कि मोदी सरकार का नागरिकता संशोधन अधिनियम (ब।।) पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को संरक्षण देने के लिए ही लाया गया था, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने इसका विरोध कर सड़कों पर आंदोलन कराए। फारूकाबाद का ध्वस्त गुरुद्वारा साहिब आज उनसे पूछ रहा है कृ अगर ब।। गलत था, तो पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदू–सिख कहाँ जाएं? चुग ने स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू–सिख आस्था पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी।

पंजाब कांग्रेस में टूट की आहट, अमित शाह के दरबार पहुंचे रंधावा, इधर वड़िंग से खफा चन्नी ने बुलाई 25 नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग

चंडीगढ़। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर मची हलचल के बाद अब पंजाब में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के अंदर एक बड़ी टूट के आसार नजर आ रहे हैं। राज्य में फरवरी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी के भीतर बगावत का बिगुल बज चुका है। एक तरफ जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता और गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुपचुप मुलाकात कर सियासी पारा चढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष न बनाए जाने से नाराज पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी पार्टी हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

पंजाब की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुरदासपुर के कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा अचानक गुपचुप तरीके से दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक अहम मुलाकात की है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस मुलाकात के दौरान रंधावा भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ के साथ नजर आए। कांग्रेस सांसद की भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार के साथ हुई इस गुप्त बैठक के बाद से ही पंजाब के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि रंधावा जल्द ही कांग्रेस का हाथ छोड़कर कोई बड़ा सियासी कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस आलाकमान ने हाल ही में लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी (च्च्ब्ब्) के अध्यक्ष पद पर बरकरार रखने का फैसला किया है। हाईकमान के इस फैसले से राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं में भारी नाराजगी है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर अपनी दावेदारी मजबूत मान रहे पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस फैसले से खासे आहत बताए जा रहे हैं।

राजा वड़िंग को दोबारा कमान सौंपे जाने के विरोध में चन्नी ने अब खुलकर बगावती तेवर अपना लिए हैं और अपने घर पर नेताओं का जमावड़ा बुलाकर हाईकमान को अपनी ताकत का अहसास कराना शुरू कर दिया है। नाराज चल रहे पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अपने मोरिंडा स्थित आवास पर कांग्रेस नेताओं की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसे राजनीतिक जानकार उनका शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, मंगलवार 11 अगस्त 2026 | पृष्ठ-6

आंगनवाड़ी केंद्र में लौटे बच्चों को दलित हेल्पर का बनाया खाना मिला

राजनगर १०/०८ (संवाददाता): केंद्रपाड़ा ज़िले के एक गांव के आंगनवाड़ी सेंटर में तीन महीने से चल रहा जाति का झगड़ा सोमवार को खत्म हो गया, जब ऊंची जाति के बच्चे सेंटर में वापस आए और एक दलित महिला हेल्पर का बनाया खाना खाया। रजिस्टर्ड 20 बच्चों में से 16 अपने माता-पिता के साथ घालिमाला ग्राम पंचायत के नुआगांव गांव के आंगनवाड़ी सेंटर आए और हेल्पर का बनाया खाना खाया, जबकि जो बच्चे नहीं आए, उन्होंने बीमार होने की बात कही।

शर्मिष्ठा सेठी, एक दलित महिला, को हेल्पर के तौर पर अपॉइंट करने के बाद से आंगनवाड़ी सेंटर पिछले साल 21 नवंबर से बंद था, और कई ऊंची जाति के परिवारों ने अपने बच्चों को सेंटर भेजने या प्रेग्नेंट महिलाओं और दूध पिलाने वाली मांओं के लिए सरकार की तरफ से दिए जाने वाले पौष्टिक खाने की चीज़ें लेने से भी मना कर दिया था। जाति विवाद से पूरे देश में गुस्सा फैल गया, और यह मामला पार्लियामेंट में भी उठा, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने काम की जगह पर जाति के आधार पर भेदभाव पर चिंता जताई। सोमवार को, केंद्रपाड़ा चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर दीपाली मिश्रा और राजनगर ब्लॉक धरुब चरण साहू बच्चों का स्वागत करने के लिए आंगनवाड़ी सेंटर पर मौजूद थे। मैंने बच्चों को रागी के लड्डू परोसे।

बाद में, मैंने चावल और 'दलमा' (सब्ज़ी की करी) बनाकर बच्चों को परोसा। उन्हें खाना खाते देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वे खिलौनों से भी खेले, जिससे सेंटर में जान आ गई, जो लगभग तीन महीने से वीरान पड़ा था, सेठी ने कहा। मुझे उमीद है कि गांव में जाति का भेदभाव अब अपना बुरा रूप नहीं दिखाएगा, उन्होंने आगे कहा। सीडीपीओ ने कहा कि बच्चों ने, अपने गार्जियन के साथ, सेंटर में खुशी के पल बिताए। मिश्रा ने कहा, शर्मिष्ठा सेठी को हेल्पर बनाने पर कुछ गांववालों की असहमति की वजह से सेंटर लगभग तीन महीने तक बिना बच्चों के चला। अब, रौनक वापस आ गई है। जो बच्चे नहीं आए, उनके बारे में सीडीपीओ ने कहा कि वे ठीक नहीं हैं इसलिए वे नहीं आ सके। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि जो बच्चे नहीं आए थे, वे मंगलवार को सेंटर आएंगे क्योंकि झगड़ा सुलझ गया है। लोगों ने मतभेदों को पीछे छोड़ने का फैसला किया है। यह खुशी की बात है। राजनगर के ब्लॉक धुरबा चा रान साहू ने कहा, यह मामला अब पुरानी बात हो गई है। मुझे उम्मीद है कि गांववालों के बीच भाईचारा बना रहेगा। स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की मेंबर सुजाता नायक ने बच्चों के सेंटर में वापस आने की तारीफ की और कहा कि कमीशन बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के मकसद से एक अवेयरनेस ड्राइव शुरू करेगा। केंद्रपाड़ा के सब-कलेक्टर अरुण नायक ने पहले कहा था कि स्टेकहोल्डर्स की मौजूदगी में मामला सुलझ गया है।

गांजा तस्करी नाकाम, 16 लाख रुपये का प्रतिबंधित सामान जब्त

जाजपुर १०/०८ (संवाददाता): नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, ओडिशा के जाजपुर जिले में एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक पिकअप गाड़ी से करीब 1 क्विंटल और 60 किलोग्राम गांजा ज़ब्त किया, जब इस प्रतिबंधित सामान की तस्करी बौध से पश्चिम बंगाल की जा रही थी। यह ऑपरेशन कुआखिया-पनिकोइली रोड पर किया गया, जहाँ एक्साइज अधिकारियों ने खास जानकारी मिलने के बाद गाड़ी को रोका। अधिकारियों के अनुसार, तस्करों ने पकड़े जाने से बचने के लिए गांजे को पानी की बोतलों की खेप के रूप में छिपाकर ले जाने की कोशिश की। हालांकि, सतर्क एक्साइज टीम ने पिकअप गाड़ी को जांच के लिए रोका और उसके अंदर छिपाकर रखी गई भारी मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद किया। तस्करी ऑपरेशन में शामिल दो लोगों को मौके पर ही गिरफ़्तार कर लिया गया। ज़ब्त किए गए गांजे की कीमत अवैध बाज़ार में लगभग 16 लाख रुपये बताई जा रही है। तस्करी के लिए इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी को भी ज़ब्त कर लिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर नारायण बेहरा ने कहा, हमें जाजपुर में गांजा तस्करी के बारे में खास जानकारी मिली थी और हमने तुरंत कार्रवाई की। गाड़ी को रोका गया और लगभग 1.5 क्विंटल गांजा, जिसकी कीमत लगभग 16 लाख रुपये है, ज़ब्त किया गया। बालासोर की ओर जा रही गाड़ी को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, जिससे तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। रैकेट के अन्य सदस्यों की पहचान करने और प्रतिबंधित सामान के स्रोत और मंज़िल का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों को शाबाश पुरस्कार प्रदान किया गया

राउरकेला १०/०८ (संवाददाता): राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के मंथन सभागार में आयोजित एक विशेष पुरस्कार समारोह में सेल, राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी) के निदेशक प्रभारी (डीआईसी), श्री आलोक वर्मा ने अलग-अलग कामों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सेल शाबाश पुरस्कार योजना के तहत संयंत्र के 5 वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक (खान विकास एवं सीएमएलओ), श्री बी के गिरि, कार्यपालक निदेशक (वर्क्स), श्री विश्व रंजन पलाई कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, कार्यपालक निदेशक (परियोजनाएं), श्री सुदीप पाल चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए, डीआईसी ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और आरएसपी में परिचालन उत्कृष्टता को चलाने में उनके समर्पण, अभिनव दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस तरह की मान्यता न केवल व्यक्तियों को प्रेरित करती है बल्कि टीमों को प्रदर्शन के उच्च मानकों के लिए प्रयास करने के लिए भी प्रेरित करती है। पुरस्कार विजेताओं में महाप्रबंधक (एमआरडी), श्री एस के भुयान, महाप्रबंधक (पीडी), श्री जी बी मिश्रा, महाप्रबंधक (पीएल-ओडी), श्री एस बड़पांडा, उप महाप्रबंधक (विज़ एवं लेखा), श्री डी क सिंह और सहायक महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन - खरीद), श्री बिपिन नारायण शामिल थे।

बीजेडी की पूर्व विधायक रासेश्वरी पानीग्रही का निधन

संबलपुर १०/०८ (संवाददाता):ओडिशा की पूर्व ब्लॉकऔर मशहूर डॉक्टर रासेश्वरी पानीग्रही का सोमवार को संबलपुर ज़िले में उनके घर पर निधन हो गया, उनके डॉक्टर ने बताया। वह 79 साल की थीं और अविवाहित थीं। पानीग्रही का न्यूरोलॉजिकल दिक्कतों की वजह से इलाज चल रहा था। रविवार को उनकी हालत तब और बिगड़ गई जब वह संबलपुर शहर के शांति नगर में अपने घर पर थीं। डॉक्टर ने कहा, क्योंकि पानीग्रही अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहती थीं या उन्हें वेंटिलेटर पर नहीं रखा जाना चाहती थीं, इसलिए उनका घर पर ही इलाज चल रहा था। वह रविवार तक दिमागी तौर पर एक्टिव थीं। लेकिन आज उन्हें नींद आ रही थी। उनकी मौत रात करीब 8.50 बजे हुई। पानीग्रही 2014 में बीजू जनता दल (ब्लॉक्ष्ट) के टिकट से संबलपुर सीट से एक बार राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई थीं। हालांकि, उन्होंने 2024 में ब्लॉक्ष्ट से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। पश्चिमी ओडिशा की मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट पानीग्रही अपने समर्पण और इंसानियत की सेवा, खासकर गरीबों के लिए, के लिए जानी जाती हैं। वह संबलपुर के कई सामाजिक-सांस्कृतिक और धार्मिक संगठनों से जुड़ी थीं और सामाजिक कामों में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक ब्लॉक पोस्ट में कहा कि उन्हें पाणिग्रही के निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, जो संबलपुर के एक वरिष्ठ नेता और एक जाने-माने डॉक्टर थे। उन्होंने दुखी परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और भगवान जगन्नाथ से दिवंगत आत्मा के स्वर्गवास की प्रार्थना की। पूर्व ब्लॉक का अंतिम संस्कार मंगलवार को परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा।

मयूरभंज में अलग-अलग सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, तीन घायल

मयूरभंज २३/०२ (संवाददाता): ओडिशा के मयूरभंज जिले में दो अलग-अलग रोड एक्सीडेंट में दो लोगों की जान चली गई और तीन अन्य घायल हो गए। पहला एक्सीडेंट बिसोई पुलिस लाइन के तहत भोलाबेड़ा चक के पास हुआ।

शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिससे जोरदार टक्कर हुई। एक सवार, जिसकी पहचान रवि मुंडा के तौर पर हुई, की गंभीर चोटों के कारण मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार तीन अन्य लोग एक्सीडेंट में घायल हो गए।

स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घायलों को पहले फर्स्ट एड दिया गया, फिर आगे के इलाज के लिए रायरंगपुर के सब-डिविजनल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनकी हालत स्थिर बताई गई है, हालांकि वे अभी भी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में हैं।

एक्सीडेंट की बढ़ती संख्या ने चिंता बढ़ाई उसी दिन एक और घटना में, बादामपहाड़ पुलिस स्टेशन के तहत दलकी चक के पास एक मोटरसाइकिल पिकअप वैन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले की पहचान बहलदा पुलिस लाइन के लोकनाथपुर गांव के रहने वाले सुनील महाकुड़ के तौर पर हुई है। चश्मदीदों ने बताया कि एक्सीडेंट के तुरंत बाद पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से भाग गया।

बाद में पुलिस मौके पर पहुंची, गाड़ी को कब्ज़े में लिया और बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। दोनों एक्सीडेंट के सिलसिले में अलग-अलग केस दर्ज किए गए हैं, और हादसों की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। अधिकारियों ने गाड़ी चलाने वालों से सावधानी बरतने और ऐसे दुखद हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

रुशिकुल्या नदी के पास इरावदी डॉल्फ़िन मिलीं

गंजम १०/०८ (संवाददाता): गंजम जिले में रुशिकुल्या नदी का मुहाना, जो खतरे में पड़े ऑलिव रिडले कछुओं के बड़े पैमाने पर घोंसले बनाने के लिए जाना जाता है, इरावदी डॉल्फ़िन के लिए एक संभावित रहने की जगह पाया गया है, एक फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर ने मंगलवार को यह जानकारी दी। फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने खल्लीकोट फ़ॉरेस्ट रेंज के तहत बटेश्वर के पास समुद्री मैमल्स की गिनती के दौरान ऐसी 13 गंभीर रूप से खतरे में पड़ी डॉल्फ़िन का झुंड देखा है, उन्होंने बताया। तीन दिन की डॉल्फ़िन जनगणना 20 से 22 जनवरी के बीच की गई थी। फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर ने बताया कि सर्वे के दौरान, डॉल्फ़िन को पानी की सतह पर आते और इलाके में ग्रुप में घूमते हुए देखा गया। खल्लीकोट रेंज के असिस्टेंट कंज़र्वेटर ऑफ़ फ़ॉरेस्ट दिज़्या शंकर बेहरा ने कहा, गणना से पता चला है कि पुरुनाबांध-प्रयागी इलाके में डॉल्फ़िन की अच्छी-खासी मौजूदगी है।

अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले, फ़ॉरेस्ट ऑफ़िसर्स को इलाके में बॉटलनोज़ और हंपबैक जैसी दूसरी तरह की डॉल्फ़िन मिली थीं। उन्होंने कहा कि चिलिका झील में बड़ी संख्या में देखी गई इरावदी डॉल्फ़िन शायद रुशिकुल्या नदी के मुहाने वाले इलाके में चली गई होंगी। आस-पास के गांवों के लोग, खासकर मछुआरे, पिछले कुछ सालों में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जो बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने के लिए आते हैं।

एसीएफ ने कहा, अब गांव वाले डॉल्फ़िन और पंख वाले मेहमानों जैसे दूसरे पानी के जानवरों की सुरक्षा के बारे में भी जानते हैं। हम दूसरे जानवरों और पक्षियों के अलावा ओलिव रिडले की सुरक्षा के लिए गांव वालों में जागरूकता पैदा कर रहे हैं।

वाइल्डलाइफ़ एक्टिविस्ट रवींद्र नाथ साहू ने कहा कि नदी के मुहाने के पास इरावदी डॉल्फ़िन के दिखने से रुशिकुल्या एस्चुएरी की बायोडायवर्सिटी से भरपूर इकोसिस्टम के तौर पर अहमियत और बढ़ गई है।

यह एस्चुएरी ओलिव रिडले कछुओं के बड़े झुंड के लिए मशहूर है, क्योंकि फरवरी के तीसरे हफ़्ते में हज़ारों समुद्री जीव अपने बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने के लिए इस जगह पर आते हैं। उन्होंने कहा कि इस जगह पर कई माइग्रेटरी पक्षी भी आते हैं, खासकर हर सर्दियों में बार-हेडेड गीज़। क्योंकि इस इलाके को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, साहू ने सरकार से पानी में रहने वाले अलग-अलग जानवरों की सुरक्षा और बचाव के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की।

आरएसपी के स्टील मेल्टिंग शॉप-1 ने कन्वर्टर लाइनिंग लाइफ में बनाया नया कीर्तिमान

राउरकेला १०/०८ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के स्टील मेल्टिंग शॉप-1 (एसएमएस-1) के कन्वर्टर 'ज़्यू' ने 9 फरवरी, 2026 को कन्वर्टर लाइनिंग के जीवनकाल में नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसने अगस्त 2014 में स्थापित 2,125 हीट्स के पूर्व रिकॉर्ड को पार कर लिया। उल्लेखनीय है कि, कन्वर्टर अभी भी सुचारु रूप से चल रहा है।लाइनिंग के जीवन काल में यह उल्लेखनीय वृद्धि प्रक्रिया मानकों के कड़े नियंत्रण, अनुकूलित रिफ्रैक्ट्री प्रबंधन पद्धतियों तथा कन्वर्टर संचालन के दौरान मानक परिचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के सतत पालन से संभव हो सकी है। यह उपलब्धि परिचालन उत्कृष्टता, पाली प्रभारी एवं परिचालन समूह के प्रभावी समन्वय, ब्लोअर्स एवं लांस ऑपरेटरों द्वारा सूक्ष्म प्रक्रिया नियंत्रण तथा एसएमएस-1 के सभी कर्मियों के समर्पित टीमवर्क का प्रतिफल है।

प्रमुख योगदान देने वाले कारकों में नियंत्रित ब्लोइंग प्रक्रियाएँ, बेहतर स्लैग प्रबंधन, प्रभावी एंड-पॉइंट नियंत्रण और रिफ्रैक्ट्री लाइनिंग की समय पर गनिंग और पैचिंग शामिल हैं। एरिया प्रभारी और पाली प्रभारी द्वारा थर्मल लोड, बाथ एजिटेशन और स्लैग केमिस्ट्री की बारीकी से निगरानी, साथ ही हॉट मेटल और स्क्रैप की गुणवत्ता पर अनुशासित नियंत्रण ने स्थानीय घिसाव को कम करने और लाइनिंग कैंपेन की अवधि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह सफलता ऑपरेशंस, रिफ्रैक्ट्री, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अनुरक्षण, एलडीबीपी, ब्लास्ट फर्नेस और आरसीएल टीमों के बीच बेहतर समन्वय के कारण भी संभव हुई, जिससे पूरे अभियान के दौरान स्थिर और सुसंगत प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ।

कन्वर्टर %ज़्यू% की विस्तारित लाइनिंग लाइफ के परिणामस्वरूप कन्वर्टर की उपलब्धता में सुधार हुआ है, प्रति हीट रिफ्रैक्ट्री की खपत कम हुई है, रिलाइनिंग डाउनटाइम कम हुआ है, और एसएमएस-1 संचालन की उत्पादकता और लागत दक्षता में समग्र वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि, एसएमएस-1 भारतीय इस्पात उद्योग की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित कन्वर्टर शॉप्स में से एक है। 1959 में स्थापित एसएमएस-1 को एशिया की पहली और विश्व की दूसरी एलडी कन्वर्टर शॉप्स होने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है।

मुख्य महाप्रबंधक (एसएमएस ब्लॉक 1), श्री बी सुनील कार्था के मार्गदर्शन में विभाग न्यूनतम स्वचालन के बावजूद अनुशासित कार्यप्रणाली, सशक्त प्रक्रिया नियंत्रण और कुशल मानव संसाधन के बल पर उत्कृष्ट परिचालन क्षमता का निरंतर प्रदर्शन कर रहा है।